(viii) Financial Assistance For Setting up a paper Mill in Tripura

SHRI AJOY BISWAS (Tripura West): Under Rule 377, I make the following statement :

The forests of Tripura are very rich in Bamboo and Hard wood. In view of this, the Government of Tripura decided to explore the feasibility of setting up a Paper Mill in Tripura. A project report was prepared which established viability of the Paper Mill. The estimated cost of the setting up of the Paper Mill is Rs. 97 crores and it has employment potential for about 20,000 persons directly and indirecly. Requirement of raw materials of 300 tonnes per day is estimated to be 2,38,000 tonnes of bamboos per year. According to the pre-investment survey 5 lakh tonnes of bamboo per year can be extracted from the natural bamboo forests; availability of sufficient water from the river Manu, easier transport of raw materials by river, the site of the mill was selected at Fatikray which will be well connected by railway line in near future. The letter of intent for setting up a Mill for manufacturing of bleached pulp, printing and writing papers with an annual capacity of 82,500 tonnes was issued by the Government of India on 23.4. 1985. The expenditure incurred on the project so far is about 16 lakhs for consultants fees etc. The need of a Paper Mill Project in Tripura being a backward and under-developed State requires no explanation. I shall request the Central Government to provide fund for setting up of a Paper Mill in Tripura without further delay.

DEMANDS FOR GRANTS, 1983-84

Ministry of Home Affairs-Contd.

Mr. CHAIRMAN : The House will now resume further discussion on Hudget demands for the Ministry of Home Affairs. Shri R.P. Yadav may continue.

(Interruptions)

Mr. CHAIRMAN : Shri Yadav has to continue his speech.

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : सभापति जी, मैंने अपना नाम दिया था,7 तारीख को, मुझे बोलने को नहीं मिला ।

SHRI R. P. YADAV (Madhepura) : I was on my legs. How can you object that ?

श्री भीखा भाई : मुझे दो साल से कोई मौका नहीं मिला । मैं बीमार रहा ।

सभापति महोदय : आपका नाम नहीं लिया गया, आपको गलती लगी ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव(मधेपुरा) : सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि जून, 1980 में इंदिरा कांग्रेस ने एक व्यक्ति के हाथ को मजबूत करने का आह्वान किया था ताकि देश को सशक्त शासन दिया जा सके और देश की जनता चैन की नींद सो सके तथा देश से भ्रष्टाचार मिटाया जा सके परन्तु हालत ठीक उसके विपरीत हुई है । अपराध और भ्रष्टाचार हर पल, हर दिन, हर महीने और हर साल बढ़ते ही गए हैं । मैं आंकड़ों के आधार पर इसको सिद्ध करना चाहता हूं । 1980 के फर्स्ट क्वार्टर में थर्ड 5110 मर्डर हुए, सेकेन्ड क्वार्टर में 5508, हुए, क्वार्टर में 5869 हुए और फोर्थ क्वार्टर में 5792 हो गए ।

इसी प्रकार से मैं रेप से सम्बन्धित आंकड़े भी देना चाहता हूं । इस सरकार के समय में रेप एक आम बात हो गई है । 1980 के ही फर्स्ट क्वार्टर में रेप 753 हुए, सेकेन्ड क्वार्टर में 917 हुए और थर्ड क्वार्टर में 1393 रेप हुए ।

जहां तक रायट्स और दंगों का सम्बन्ध है, उसी वर्ष के फस्ट क्वार्टर में 2 लाख 11 हजार हुए, सेकेन्ड क्वार्टर में 2 लाख 25 हजार 11 हुए और थर्ड क्वार्टर में 2 लाख 72 हजार 54 दंगे हुए । इसी तरह से प्रोहिविशन की तहत

फर्स्ट क्वार्टर में 27,482 केसेज हुए, सेकेन्ड क्वार्टर में 98,408 केसेज हुए और थर्ड क्वार्टर में 1,32,049 केसेज हुए। यह आंकड़े स्वयं बोलते हैं कि हर पल, हर दिन, हर महीने और हर साल क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही मैं यह बात कह रहा हूं, यदि मन्त्री जी चाहें तो कन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं।

अब मैं अपने प्रदेश, बिहार के सम्बन्ध में कुछ बतलाना चाहूंगा। आज बिहार की स्थिति बदतर है। वहां पर जान व माल की कोई सुरक्षा नहीं है। ला ऐंड आर्डर वास्तव में वहां पर फेल हो गया है। जरूरत तो यह है कि भारत सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करे। आज वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनकी हालत यह है कि गोपालगंज के डी एम को बम से उड़ा दिया गया लेकिन उसके बावजूद बिहार सरकार कहती है कि बिहार की ला ऐण्ड आर्डर की स्थिति चिन्ताजनक नहीं है। इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है।

इसके बाद मैं कुछ अपने जिले के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा। इस बारे में मैंने एकाध बार गृह मन्त्री जी से जिक्र भी किया है कि अगर रक्षक ही भक्षक हो जाएं तो भगवान ही जनता की रक्षा कर सकते हैं। वहां पर मन्त्रिगण क्रिमिनल्स को पालते हैं और उन्हीं के बल पर जीतते हैं। मैं दो एक उदाहरण देना चाहूंगा कि किस प्रकार की स्थिति वहां पर विभिन्न जिलों में है। सहरसा जिला जहां से मैं आता हूं, वहां पर एक सरकारी कालेज हैं जिसके हास्टेल पर क्रिमिनल्स का आधिपत्य है। प्रशासन तन्त्र का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जा सकता है। सुपरिन्टेन्डेन्ट भी मुझ से कह रहे थे कि वे वहां पर नहीं जा सकते हैं और अगर वे किसी लड़के को एलाट भी करते हैं तो उसको क्रिमिनल्स बाहर फेंक देते हैं। सहरसा कमिश्नरी का हैडक्वार्टर भी है। एक सियाराम यादव को वहां पर खदेड़ कर गोली मारी गई लेकिन हत्यारों को आज भी मन्त्री जी का संरक्षण मिल रहा है। प्रशासन का मुख्य भाग दारोगा होता है, जो कि ला एन्ड आर्डर को एन्फोर्स करता है, उसको उसी शहर में दिन में छुरा मारा गया लेकिन आज तक क्रिमिनल्स का कुछ नहीं हुआ। सहरसा से पांच किलोमीटर पर एक जगह मरना है जहां पर 11 मुसलमान बच्चों तथा औरतों को कत्ल कर दिया गया। जिसके द्वारा कत्ल किया गया, वह वहां के एक वरिष्ठ मन्त्री के इलैक्शन एजेंट हुआ करते हैं, लेकिन आज तक इनका कुछ नहीं हुआ है। यह बिहार की हालत है। संसार के इतिहास में यह कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि जब दो देश आपस में लड़ते भी हैं, तो भी रेडक्रास की गाड़ी पर कोई गोली नहीं चलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुलाब यादव नाम का व्यक्ति जिसको अस्पताल में भरती किया गया, क्रिमिनल्स द्वारा दिन-दहाड़े सिर काट कर ले जाया गया। एफ० आई० आर० में नाम है; लेकिन आज तक वे बाहर घूम रहे हैं। इस बारे में मैंने गृह मन्त्री जी को कहा था, उन्होंने कहा कि इसको स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर किस तरह से वह प्रदेश चलेगा। पुलिस के लिए जान बहुत सस्ती है। मुरलीगंज हमारे क्षेत्र में पड़ता है! वहां पुलिस द्वारा गोली चलाई गई उसमें तीन लड़के मारे गए। मैं आप से कहना चाहता हूं कि पुलिस की गोली से मरने वाले को कम से कम एक लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए, जैसा कि ऐक्सीडेंट में प्रावधान है।

अब मैं आता हूं, इस देश की राजधानी दिल्ली पर। वास्तव में यदि इसको अपराध की राजधानी कहा जाए, तो वह सही बात होगी श्री रामविलास पासवान के 30.3.83 के प्रश्न के जवाब में मन्त्री जी ने कहा है कि हत्याओं के मामलों की संख्या में वृद्धि के अतिरिक्त दिल्ली

में कुल मिलाकर अपराध कम हुए हैं। मैं इसको गलत साबित करना चाहता हूं, आपके ही आंकड़ों के आधार पर। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। दिल्ली में 1981 में 21 डकैतियां हुई और 1982 में 22 डकैतियां हुई हैं। मर्डर्स में आपने स्वयं माना है कि काफी बढ़ोतरी हुई है। 1981 में 199 और 1982 में 236 ऐसे मामले हुए हैं। मिसलेनियस क्राइम्स 1981 में 9,113 और 1982 में 9,400 केवल यह कह देना कि सब में कटौती हुई है, उचित नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि दिल्ली की पुलिस क्या दिल्ली वालों की जान-माल की रक्षा करने में सक्षम हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की पुलिस अक्षम रही है। 1982 का वर्ष सबसे ज्यादा खराब रहा है। इस वर्ष में डाउरी डैथ्स ज्यादा हुई है, अन्तरराष्ट्रीय संवाद एजेंसी के संवाददाता की हत्या हुई; कुवैत के दूतावास के सेक्रेटरी की हत्या हुई, सफदरजंग के एक व्यापारी की पार्सल बम्ब से हत्या हुई—लेकिन आज तक कोई जानकारी नहीं हो पाई है। पैट्रोलपम्प की लूट, डाकखानों और बैंकों में डकैतियों की सबसे ज्यादा बढोतरी हुई है। औरतें दिल्ली में स्वतन्त्र रूप से नहीं घूम सकती है। दिन-दहाड़े औरतों के गले से चैनें छीन ली जाती हैं। क्रिमिनल्स गाड़ियों में घूमते हैं। कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस की गलती के चलते अकालियों द्वारा संसद पर हमला हुआ। पुलिस की गोली से चार अकाली मारे गए। लेकिन आज्ञा किसने दी, यह आज तक नहीं पता चला है। 1982 में हर तीस मिनट में एक चोरी हुई है। दर्जनों बम्ब फूट चुके हैं, लेकिन आज तक नहीं पता चल सका है, न इसको रोका जा सका है। आदमी का पुलिस पर से विश्वास हटता जा रहा है। पुलिस कहती है कि 50 प्रतिशत डकैतियां अनरिजालब्ड है और 22 प्रतिशत ब्लान्ड मर्डर हैं। इन्हीं की पुलिस कहती है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मैं पूछता हूं इन बढ़ते हुए अपराधों का कारण क्या है ? मुख्य कारण यही है कि पुलिस प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। पिछले दिनों मन्त्री जी ने कहा था कि ऐसी बात नहीं है। क्या वह बतलायेंगे अभी पहाड़-गंज में आगजनी के मामले में पुलिस आयुक्त की जो सार्वजनिक बेइज्जती हुई, यह हस्तक्षेप नहीं था तो क्या था ? एक पुलिस के डी० आई० जी० जो बिहार के थे, राजनीतिक कारणों से उनका तबादला किया गया। पुलिस आयुक्त भिण्डर साहब का यहां से तबादला किया गया, इसलिए कि वह इनके गलत आर्डर्ज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन बातों को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज पुलिस प्रशासन में काफी राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, जिसके कारण क्राइम्ज बढ़ते जा रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम को फिर से रिव्यू किया जाय। वास्तव में वह सक्सैसफुल हो रहा है या नहीं, यदि नहीं हो रहा है तो दूसरी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि यहां के लोग यह समझ सके कि उनका जानोमाल सुरक्षित है।

समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहता हूं। साम्प्रदायिक दंगों को लीजिये। 1978 से लेकर आज तक साम्प्रदायिक दंगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर 1978 में 230 साम्प्रदायिक दंगे हुए, 1979 में 304, 1980 में 427, 1981 में 319, 1982 में 474 दंगे हुए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो इस तरह से साम्प्रदायिक घटनायें हो रही हैं उनके बारे में सरकार क्या करना चाहती है ? एक नई बात जो इस समय सामने आ रही है, वह यह है कि इस से पहले जो साम्प्रदायिक दंगे होते थे, उन में ऐसे तत्व होते थे जो उनको कराते थे, लेकिन अब मुरादाबाद को, मेरठ को लें, पुलिस और माइनारिटीज वालों से झगड़ा होता है जिसमें पुलिस गोली चलाती है। मैं गृह मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनसू-

चित जनजातियों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, है, औरतों पर अत्याचार बढ़ रहा है। यवतमाल के बारे में अभी मार्च 30 के अखबार में आया है—वहां 14 हरिजन लड़कियों के साथ रेप किया गया, जिनके बारे में सरकार खामोश है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और इन चीजों के खिलाफ कार्यवाही करे।

समय कम है, अब मैं मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। यह सरकार पिछड़ा-वर्ग विरोधी सरकार है, इस मायने कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को आये दो साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन आज तक सरकार की मन्शा स्पष्ट नहीं हुई है, सरकार में न इतनी हिम्मत है कि इस को लागू करे या यह कहे कि हम लागू नहीं करेंगे। 14 महीने तक बड़ी जद्दोजहद के बाद सदन में उस रिपोर्ट को रखा गया और कहा गया कि मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुला रहे हैं। पिछले दिनों मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ। यह सदन जानना चाहता है कि किन मुख्य मन्त्रियों ने इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में क्या स्टैण्ड लिया। यह कहा जाता है कि बाक-एन-लार्ज मुख्य मन्त्रियों ने विरोध किया है। उनसे पूछते है तो वे कहते हैं कि हम ने तो पक्ष में वोट किया है। हमें तो यह मालूम हुआ है कि मुख्य मन्त्रियों ने कहा है कि यह हमारा बेबी नहीं है, आप का बेबी है, इस को सम्भालो। हम तो बाइ-एन-लार्ज अपने यहां रिजर्वेशन लागू कर चुके हैं, अब तो केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में यह रिजर्वेशन लागू होना चाहिये। अब यह आप के करने की जरूरत है। मैं तो यह समझता हूं कि इस तरह से न तो इस सरकार में हिम्मत है और न यह करना चाहती है।

यह कमीशन देश के विभिन्न भागों में घूमा है, इस ने देश की विभिन्न सरकारों के विचारों को लेकर, संस्थाओं के विचारों को लेकर, व्यक्तियों के विचारों को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है कि जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि देश में 52 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं। साढ़े बाइस प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं और 11 प्रतिशत मुसलमान हैं इस तरह से यदि साढ़े-पिच्यासी प्रतिशत लोगों के अधिकारों को नजर अन्दाज किया जाय तो मैं यह मांग करता हूं, बल्कि चेतावनी देना चाहता हूं, यदि समय रहते आप नहीं समझेंगे तो जिह तरह से यह लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनका गुस्सा न यह सरकार बरदाश्त कर सकेगी और न इनकी पार्टी बरदाश्त कर सकेगी। इसलिए आवश्यक यह है कि उनकी जो वाजिब मांगें हैं, वे अलगाव की बात नहीं करते हैं, वे कहते हैं कि जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं वे उनको दो। लेकिन इतना अवश्य चाहते हैं कि इस सरकार के प्रशासन में वे वास्तव में सहभागी अवश्य हों, जिनके लिए कि इस देश में यह जनतन्त्र है। साढ़े-बाइस प्रतिशत जो शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स को दे रहे हैं, वे इसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं, 5 परसेन्ट ही पूरा कर पाये हैं। तो फिर जो लोग 52 परसेंट हैं उनको आप क्यों रिजर्वेशन देना चाहते हैं ? यह दलील दी जाती है कि इस से एफीशियेंसी घट जाएगी। आपका ही मानना है कि तमिलनाडु में जहां पर कि रिजर्वेशन लागू है वह बेस्ट एडमिनिस्टर्ड स्टेट है। इस पर भी यह कहना कि एफीशियेंसी घट जाएगी, यह गलत होगा। रिजर्वेशन करने से एफीशियेंसी नहीं घटेगी। ऐसा तर्क देने से तो आप किसी को भी रिजर्वेशन नहीं देना चाहेंगे। मैं यह नहीं कहता कि आप हरिजनों को रिजर्वेशन न दें, महिलाओं को न दें। लेकिन आप मण्डल कमीशन ने जो बात कही है उसको भी मानें। मण्डल कमीशन ने सारी बातों को, ला कोर्ट्स के डिसीजंस को मद्देनजर रखते हुए कम से कम आरक्षण करने की सिफारिश की है। इसलिए आप कम से कम उसकी सिफारिश को तो तुरन्त मानें। बैकवर्ड क्लासिज के लिए तो वास्तव में

52 परसेंट रिजर्वेशन होना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में वे यह मांग करेंगे। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि वह मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी लागू करे।

जहां तक मंडल कमीशन की बात है, मैं एक बात को मनुस्मृति से उद्धृत करना चाहता हूं। मनुस्मृति वास्तविक में अपर कास्ट्स के लिए, खास कर के ब्राह्मण वर्ग के लिए है। मनुस्मृति (जिसको वे अपना अस्त्र बनाये हुए हैं,) **उसके बारे में एक लाईन बताना चाहता हूं...

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति जी, इस शब्द को निकाल दिया जाय।

MR. CHAIRMAN : I will go through the proceedings. I will look into it. Mr. Yadav, kindly wind up. The time is running short. You must be judicious. You have already taken so much of time.

No Member should bring in the point of; a Holy Book like this. I will look into this.

Mr. Yadav, you may continue.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मनुस्मृति में कहा गया है...

(व्यवधान)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : Whatever he likes to read, he may read. But the words which he has used ** should be, deleted.

SHRI R.P. YADAV : That is not unparliamentary (*Interruptions*)

मैं एक बात कहना चाहता हूं...

MR. CHAIRMAN : Please listen to me. I am on my legs.

आचार्य भगवान देव : सभापति जी, मनुस्मृति को ये समझते नहीं हैं...

MR. CHAIRMAN : Against any Holy Book undignified word should not be used at any cost. (*Interruptions*) It is for me to interpret, and not for you.

आचार्य भगवान देव : आप मनुस्मृति का एक शब्द नहीं पा सकते हैं।

MR. CHAIRMAN : No more. I have given my ruling on the subject.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मनुस्मृति में कहा गया है

"Slaying a Shudra by a Brahmin is equivalent merely to the killing of a cat, a mangoose, a blue jay, a frog, a lizard, an owl or a crow....."

यदि यही मनुस्मृति है तो हमें अदब के साथ कहना पड़ेगा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह से इसमें शुद्र की किल्ली से तुलना की गयी है। इसलिए हम चाहते हैं

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : क्या मार्क्स ने सब ठीक कहा है या लेनिन ने सब ठीक कहा है ? आप यह कह सकते हैं कि अछूतों के साथ शूद्र कहकर दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान) किसी धर्म में चार शादियों की इजाजत दी गई है। आप चार शादियां करके दिखाइए।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : बागड़ी जी को समझने में दिक्कत हो रही है। मैं इसको कोट करूंगा।

(व्यवधान)

**Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN : Any word or any aspersion that can be considered in terms of being undignified will be expunged. That is for me to decide.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने सिर्फ इसमें से उद्धृत किया है। केवल मैंने कोट किया है।

श्री रामलाल राही : कोई भी धर्म शास्त्र चाहे वह जितने बड़े समाज का हो, अगर वह मानवता के विरुद्ध है तो हम उसका विरोध करेंगे। उसको फाड़ेंगे, नोचेंगे, जलाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : यह जगह जलाने की नहीं है। यहाँ पर आप नहीं जला सकते। यहां पर किसी धर्म का विरोध नहीं कर सकते।

श्री रामलाल राही : मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री प्रताप भानु शर्मा : (विदिशा) आप अपने घर में बैठकर जलाइए, यह जगह नहीं है जलाने की या फाड़ने की।

श्री रामलाल राही : ऐसे शास्त्रों को मान्यता नही दी जाएगी।

MR. CHAIRMAN : Undignified expressions will be expunged.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : May I make a suggestion ? He is a very experienced Parliamentarian. To strengthen his case he need not denigrate others. Let him put forward his case. Let him not indulge in anything which wounds the sentiments of other members of the House. I only make an appeal to refrain from this as far as possible. Let him make out his own case.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : He has accepted it.

(*Interruption*)

MR CHAIRMAN : Leave it. The matter is now finished. Ms Yadav, you must now conclude.

SHRI R. P. YADAV : I am just concluding, Sir.

MR. CHAIRMRAN : This tailpiece was rather tricky. Kindly conclude.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : इसलिए मैं कह रहा हूं। सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि "मनुस्मृति" की जगह "मण्डलस्मृति" प्रतिष्ठापित की जाए। इससे हिन्दुस्तान के 85 प्रतिशत दबे और कुचले लोगों का कल्याण होगा और उनकी बढ़ोतरी हो सकेगी। अन्त में मैं आसाम के बारे में थोड़ा सा कहकर समाप्त करूंगा।

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You please round it off. I will not ring the bell. I have got all regard for you. You should finish now. You have said enough.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Kindly finish in one minute.

SHRI R. P. YADAV : Anything that is controversial, that is wrong, will be expunged.

(*Interruptions*)

सभापति जी, मैं मानता हूं कि आसाम का जो चुनाव हुआ, वह हमारे संविधान पर बहुत बड़ा धोखा है। यह बात ठीक है कि हमारी पार्टी ने चुनाव में भाग लिया है इस विश्वास के साथ कि जो इलैक्शन कमीशन ने नियम और कानून बनाए हैं उनके मुताबिक चुनाव करवाए जायेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : पार्टी का नाम बता दीजिए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : आप छोटे आदमी हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपेरा) : आपने उनको छोटा आदमी क्यों कहा ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : नये मियां को ज्यादा प्याज नहीं खानी चाहिए। हमारे प्रदेश से एक मंत्री जी चुनाव में गए थे। वे स्वयं कह रहे थे कि सड़क पर उन्हें एक कुत्ता भी नहीं मिला। रात को एक केन्डीडेट मशीनगन के साथ उनसे मिलने आए। लेकिन दस मिनट में कहां चले गये, कुछ पता नहीं चला। मैं यह कह सकता हूं कि वे विधान सभा में चुनकर आये, हैं। वहां असेम्बली को भंग किया जाना चाहिए, उसका कोई आधार नहीं है।

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, मेरा नाम भी गया हुआ है। मैं सिर्फ पांच मिनट बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : जिनका नाम लिया जाता है सिर्फ वे ही बोलेंगे। सारे नहीं बोलेंगे। आप अपने आपको कैसे नामिनेट कर सकते हैं ?

श्री भीखा भाई : मैंने सात तारीख को नाम दिया है।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। चेयर को मैं कन्ट्रोल कर रहा हूं। आप मुझे क्यों कन्ट्रोल कर रहे हैं ? जिस तरीके से नाम लिखे हुए हैं, उसी तरीके से चलाया जायेगा। आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। आपके दूसरे साथी भी तो हैं। आप क्यों टाईम खराब करते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : पार्लियामेन्टरी अफेयर्स मिनिस्टर को चाहिए कि वह कन्ट्रोल करे।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : ताऊ, तैने कभी मेरी बात मानी है ?

SHRI EUARDO FALEIRO (MORMUGAO) : Mr. Chairman, just now the Minister for Parliamentary Affairs was mentioning about how we have been cutting the time of other Ministries. I am sure I will not embarrass by taking more than a few minutes.

MR. CHAIRMAN : It is very good of you to say so. I might repeat for the benefit of Members who are going to speak. I would request them to be brief and only bring out salient points. Do not ramble around places and say something which is not pertinent.

SHRI EDUARDO FALEIRO : Mr. Chairman, I thought that I should bring through you to the notice of the House, in this debate, a very shady deal and show how things are going on and how corruption, mismanagement of money and manipulation of funds are done at high sources and by very highly placed persons. Mr. Chairman, the Home Ministry is in fact an ocean. It has a very vast machinery. But the problems with which it has to deal are no less vast. In fact, the magnitude of the problems is such that they are so gigantic and they are frightening actually. Sir, the Government has, over the years, been talking about reforms in election process, in a manner that would out particularly at the point of money power and manipulation of elections through money.

Sir, I have to make here a definite allegation concerning the collection of money which, to my mind, is for the purpose of elections ; but which, in any case, is illegal and a shady, collection of money by no less than a person than a very eminent political figure, viz. Shrimati Vijaya Raje Scindia. Before I proceed further, to cut the time on interruptions, I may say here that I have submitted, as required, before making allegations, the necessary evidence to the Speaker and to you, the Chair.

MR. CHAIRMAN : Yes.

SHRI EDUARDO FALEIRO : And I have been permitted. I will make the allegations, as you have rightly said, without rambling ; but I will be very specific and sharp.

The Scindia Devasthan Trust with its head office at Sarojini Nagar, New Delhi is administered by a Board of Trustees, and has Shrimati Vijaya Raje Sciendia as its Chairman. In the year 1980, Shri Shambhaji Rao Angre, *alias* Sardar Angre and Shrimati Sushma Singh were appointed as Trustees, but this appointment has been challenged in a Court of law.

The Trust of which we are speaking, is a public charitable registered institution, and it owns several properties all over the country, and one such property is situated at Allahbad, known as 'Sansthan Prayag', located at 164, Bai-ka-Bagh.

I will give a description. This property is connected by a large gate, and is protected by walls on all sides. In front of the gate, there is a temple of Veni Madhavji and towards east, there are other temples under a peepal tree of Shri Hanumanji, Shri Shankarji and Nandi. This is a very important religious place, and people from Allahabad and all over the country actually visit this temple for *darshan*. The property which I have mentioned, has also a *dharmshala* where outsiders stay, and which is also used on the occasions of marriages, functions and festivals.

On May 26, 1982, Shrimati Vijaya Raje Scindia who is the Chairman of this Trust obtained a Resolution for the purpose of selling this property at Allahabad, and as a result, the temples of Shri Hanumanji, Shri Shankarji and Nandi are to be sold.

Temples are to be sold by no less a person than Shrimati Vijaya Raje Scindia who makes such a hue and cry about her religious allegiances. Temples are to be sold I would like to proceed further and say-they are going to be demolished, after the sale. The temples are to be razed to the ground and cinema houses and shops are to be constructed there.

On May 26, 1982, Shrimati Vijaya Raje Scindia, who is the chairman of the Trust obtained this Resolution for the purpose of selling this property at Allahabad and as a result, the temples of Shri Hanumanji, Shri Shankarji and Nandi along with 34 residential tenements, gardens and *dharmshala* totalling an area of 1,33,188 sq. ft. are to be sold to one Shri Sitaram Pandey at the rate of Rs. 175/-per sq. metre. This rate is much below the actual market price in the locality. Actually, the market price in the locality for the same type of property is Rs. 520/-per sq. metre which amounts to Rs. 64 lakhs.

How is this property being sold ? On this I would like the Home Minister to reply, when he speaks in answer to this debate. My questions are these :

Can these temples belonging to a public religious charitable trust be sold ?

Can they be sold for the purpose of being demolished, and can cinema houses be constructed therein ?

What are the reasons ; what is the amount and what is the actual transaction ? Why is she selling a property which has a market value of Rs. 500-odd per sq. metre for Rs. 175/-per sq. metre ? Who is this Mr. Sitaram Pandey ? He is a multimillionaire. How did he get this money ? He was not a rich person a few years ago. How did he get this money ? How did he accumulate this money ?

These are all questions, to which I would like the Home Minister to address himself, and tell the House.

What is the truth and fact behind this ? As I was saying, as a result of the sale, the temples, *dharmshala* and residential tenements will be demolished, and two cinema houses and shops are to be built on this site.

An advertisement to this effect has already appeared in 'Amrit Prabhat' dated 12th November 1982. It is a paper from Allahabad. I have submitted this paper along with all other evidences to the Hon. Speaker and the Chair.

A petition has been submitted by 100 respectable citizens of Allahabad, saying that this is a shady deal and making specific allegations against certain individuals—whom I had the opportunity to mention in the cousre of my brief intervention. The allegations are against these individuals. They are that they have misused this transaction for making substantial financial profits. On the floor of this House, i.e. Lok Sabha, I urge the Home Minister to institute a thorough enquiry into how these temples and the property attached to them, belonging to a public charitable and religious trust are sought to be disposed of. So far, I understand that the sale has not been completed, but the agreement to sell has already been completed and signed, I would urge the Government and the Home

Minister to enquire into the specific allegations of mismanagement and corruption made against the Trust by the citizens of Allahabad.

This is the specific thing which I wanted to bring to the notice of the House. I am grateful to you, Sir, for the time given to me. I once again reiterate that the Government must thoroughly look into this, and assure this House that it will have a thorough enquiry into this whole matter.

MR. CHAIRMAN : You have to take responsibility for making all these allegations.

SHRI EDUARDO FALEIRO : I take full responsibility. There are affidavits. There are documents. There is a newspaper cutting. I take full responsibility. I want Government to take the responsibility of instituting an enquiry.

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदय, मैं दो दिन से इंतजार कर रहा था कि गृह मन्त्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिले। आपकी बड़ी कृपा कि आज आपने मुझे अवसर प्रदान किया।

गृह मन्त्रालय से संबंधित अनुदानों पर चर्चा ऐसे समय में हो रही है जबकि यह देश विषम परिस्थितियों से घिरा है। पूर्वी भारत में असम से लेकर नागालैण्ड तक समस्यायें घटने के बजाए बढ़ती जा रही हैं। सीमावर्ती राज्य पंजाब में नरसंहार हो रहा है। वहां की सरकार अलगाववादी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण पाने में असमर्थ है और भविष्य में भी उसके सफल होने की सम्भावना भी प्रतीत नहीं होती है। असम में वहां की जनता की इच्छा के विरुद्ध चुनाव कराए गए। वहां के चुनाव लोकतन्त्र का उपहास बन गए हैं। जो सरकार वहां बनी है उसका कोई भी मन्त्री अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहा है। यहां से जो भी लोग असम गए हैं उनका कहना है कि मंत्रिगण सशस्त्र पहरों में अपने घरों में कैद हैं। आप ही बताइये क्या ऐसी सरकार और उसके मन्त्री वहां की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे ? मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं देता है। वहां पर रोज ही हत्यायें हो रही हैं। आपको मालूम होगा हमारे दल के नेता श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा, कांग्रेस (एस) के नेता श्री शरद पवार तथा अनेक दूसरे नेतागण राष्ट्रपति से मिले थे और वर्तमान सरकार की असफलताओं का जिक्र करते हुए उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की थी। उन्होंने राष्ट्रपति जी से कहा था कि असम में जो सरकार बनाई गई है उसको भंग किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति जी जनहित को ध्यान में रखते हुए समस्याओं का समाधान करने हेतु उचित कदम उठायेंगे। आज देश की अन्दरूनी हालत हर जगह बदतर हो चुकी है। साम्प्रदायिक दंगे बराबर बढ़ रहे हैं। हरिजनों पर उतपीड़न, शोषण 35 सालों के शासन के बाद भी यह सरकार कम नहीं कर पाई है। साम्प्रदायिक हत्यायें कफ्लटा, देहुली, सीतापुर, कानपुर, बरहड़िया, पिपरा, औरंगाबाद, गया, पटना आदि इन जगहों पर हो चुकी हैं। ये घटनायें तो प्रकाश में आई हैं। जो घटनायें प्रकाश में नहीं आती है, उन पर कुछ नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ही बदत्तर है। उत्तर प्रदेश में सामूहिक हत्याकांड की घटनायें जिस तेजी से बढ़ रही है, उसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले दो वर्षों की अवधि में एटा, इटावा, मैनपुरी व कानपुर में 18 घटनाओं में 185 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जिनमें जमई में 12, बदनपुर में 11, जांख में 7, खेरिया में 9, उर्झैया फकीरपुर में 11, नगला राठ में 7, जरैला में 11, मेहमई में 20, कुवरपुर में 11, नयुआपुर में 9, दिहुली में 25, सादूपुर में 10 और दस्तमपुर में 8, रमपुरा में 6, कछपुरा में 8 और खीरी में 5 व्यक्तियों की हत्यायें प्रमुख हैं। जब इन चार जिलों की यह हालत है तो आप अन्दाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश के बाकी 56 जिलों की हालत क्या होगी ? उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन और

वहां की सरकार लगता है कि पंगु है, कुछ करने में समर्थ नहीं पा रही है अपने आप को। मुख्यमन्त्री वहां दब्बू बने बैठे हैं।

मैं आपको उत्तर प्रदेश की हालत के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं।** वहां जिस जाति का बैठाया जाए वह अपने इर्द-गिर्द अपनी ही जाति के लोगों को लगाने की कोशिश करता है। ** जब अपनी जाति के लोगों को लगायेंगे, तो अधिकारी अपने नीचे के कर्मचारियों को, एस. पी. थाने में दरोगा को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी जाति के लोगों को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक अजीब सी स्थिति हमारी उत्तर प्रदेश की चल रही है।

सभापति महोदय : आप जानते हैं कि जब बाहर का व्यक्ति इस सदन का सदस्य न हो, तो नाम लेना ठीक नहीं है।

श्री राम लाल राही : मैं माफी चाहता हूं, यदि मैंने नाम ले लिया है। ** सत्ता सीन नेता इन घटनाओं के बारे में हल्के ढंग से ले रहे हैं। हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं और इनमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। पुलिस द्वारा हत्या किया जाना मामूली बात हो गई है। अभी भी निरन्तर हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं।

मैं एक उदाहरण आपके सामने और रखना चाहता हूं—जनपद सीतापुर, थाना तैम्बोर, छुट्टन नाम का हरिजन व्यक्ति, संभवतः नवम्बर के महीने में, पुलिस ने उसको इसलिए मार दिया, क्योंकि वह एक दलाल के यहां काम करने नहीं जा रहा था। दलाल पुलिस वालों से मिलकर उसको काम पर ले जाना चाहते थे। जब वे रात को उसके घर गए और उसको आवाज दी। उसने समझा कि पुलिस उसको पकड़ने आई है और वह भागा, तो पुलिस ने उसको गोली से मार दिया। यह घटना कई अखबारों में छपी है। मैंने खुद उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक इस बात को कहा, लेकिन आज तक इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई है।

एक घटना मैं आपको और बतलाना चाहता हूं। जनपद सीतापुर में पुलिस द्वारा एक और घटना हुई है। वह है संकटा हरिजन निवासी नानकपुर। इनका दुश्मन ठाकुर था। ठाकुर ने उसके खेत में जाकर पुलिस के सामने उसको गोली मार दी। चूंकि पुलिस का वह दरोगा समझ नहीं पाया कि उसे किस लिये बुलाया है, उस ने सोचा कि शायद हमें किसी जांच के लिये लाये हैं, लेकिन जैसे ही उस आदमी को मार दिया गया, उस दरोगा ने उस ठाकुर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उस को थाने ले जाते हैं, वहां रिपोर्ट होती है और उस के बाद उस को बन्द कर दिया जाता है। इस हरिजन को जिस ठाकुर ने मारा, वह एक स्थानीय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रिश्तेदार हैं। मंत्री जी ने हमारे जिले के ही अपने एक रिश्तेदार ठाकुर को एस० पी० बनाया है। पहले उसको गढ़वाल चुनाव में ले गये थे और गढ़वाल चुनाव से आने के बाद उसको एस० पी० बनाया। जब मंत्री जी ने उस से यह कहा कि यह ठीक नहीं हुआ, इस की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिये थी, इस को एनकाउन्टर दिखाना चाहिये था, तब वह कप्तान फौरन चेता और कहा कि यह सब दरोगा ने किया है, उसी ने रिपोर्ट लिखी है। उन्होंने तुरन्त दरोगा को सस्पेण्ड कर दिया और जांच के लिये सी० ओ० को लगाया गया। उस ने सही रिपोर्ट देने की कोशिश की और कहा कि इस में दरोगा की ज्यादती नहीं है। इस पर उस सी० ओ० को भी हटा दिया गया और एक दूसरे ठाकुर को जो मुलजिम के रिश्तेदार हैं, जांच पर लगाया गया। वह जांच कर रहा है, स्थानीय लोगों पर दबाव डाल रहा है कि जांच नहीं होनी चाहिये। गवाहों को दबाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, लेकिन वे तोड़े नहीं जा सके हैं। लेकिन मंत्री का कप्तान पर काफी दबाव पड़

** Expunged as ordered by the chair.

रहा है । यह है—हरिजनों की रक्षा और सुरक्षा का नमूना ।

मैं एक और घटना आपको सुनाता हूं—शाहजहानपुर में ता० 13-14 दिसम्बर को सेहरा मऊ थाने के अन्तर्गत महुआ-पेमई गांव में पुलिस गई और एक हरिजन के मकान पर जा कर पुलिस ने कहा कि हम एक डाकू को पकड़ने आये हैं । घर में उस की औरत थी जिसका नाम रामरति था । वह आदमी घर में नहीं था, तो पुलिस उसकी औरत रामरति और गांव के कुछ लोगों को पकड़ कर ले गई । कुछ लोगों को तो एक्साइज एक्ट में बन्द कर दिया जाता है, उस औरत को रोक लिया जाता है, उसको चारपाई से बांध कर ता० 13-14 से ता० 19 तक उसके साथ बलात्कार किया गया । इस के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा गया । यह बलात्कार करने वाला कौन है—मैं आप को बतलाना चाहूंगा । यह बहुचर्चित माया त्यागी काण्ड का कुख्यात दरोगा डी० पी० गौड़ था जिसने माया त्यागी को नंगा कर के घुमाया था । इस का काम महिलाओं और गरीबों को उत्पीड़ित करना, उन को पीटना है, चूंकि उन को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, बड़े अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है, इस लिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी पता लगायें—क्या यह वास्तव में वही दरोगा है जो माया त्यागी काण्ड में सम्मिलित था जिस ने रामरति गरीब महिला के साथ बलात्कार किया ? हो सकता है उसका आदमी अपराधी हो, लेकिन महिला अपराधी नहीं थी, फिर महिला के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया ?

तीसरी घटना बड़ी दर्दनाक है—यहां एक हरिजन की हत्या कर दी गई और हत्यारा पुलिस से मिल गया, उन को कुछ रकम दे दी गई और उसके बाद उस आदमी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई । बाद में जब यह बात प्रकाश में आई तो वहां एक अखबार वाले थे—श्री मुजीबुल्ला खां—जो लोकल अखबार भी निकालते थे और प्रदेश के एक अखबार के संवाददाता भी थे । उन्होंने वहां के दरोगा से यह पूछ लिया कि चन्द्रोती गांव के श्यामदेव हरिजन की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई ? इस पर दरोगा जी आगबबूला हो गये । उस संवाददाता को बुरी तरह से बेइज्जत किया, पीटा और कई सामाजिक कार्यकर्ता जो उन के साथ थे उनको भी बेइज्जत किया । और इतने पर भी वे सन्तुष्ट नहीं हुए । यह अखबार है । अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपको पढ़ कर सुना दूं । यह दैनिक आज का समाचार छपा है । उसमें लिखा है—

"सभी वरिष्ठ अधिकारी, एम०पी०, एम० एल०ए० और मिनिस्टर बिकाऊ हैं ।"

सुन लीजिए आपका दारोगा क्या कह रहा है—"उस हमले में तो बच गये, लेकिन अब किसी कीमत पर जिन्दा नहीं बचोगे ।" यह उस पत्रकार को कहा गया जिसने कि यह पूछ लिया कि तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी । उससे यह बात कही जाती है । इस सदन के सम्मानित सांसद श्री हरिकेश बहादुर जी, जिन्होंने कि इस मामले को उठाया था, उनकी चिट्ठी भी इस समाचार पत्र में छपी है कि कितनी दर्दनाक और घृर्तता के साथ हरिजन तो मारे जा रहे हैं, सम्पादक और संवाददाता भी आज छोड़े नहीं जा रहे हैं ।

मंत्री जी कुछ सम्पादकों की घटनाएं मैं आपको और बताना चाहूंगा । यहां पर बैठने वाले संवाददाता और सम्पादक तो बड़े शहर के रहने वाले हैं, बड़ी जगहों के हैं लेकिन जो सुदूर गांवों, अंचलों और छोटे-छोटे शहरों में काम करते हैं, जिन्हें कि श्रमजीवी पत्रकार कहते हैं, उनकी आज बड़ी दुर्दशा है, उनका जीवन संकट में पड़ा हुआ है । हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने कहा है कि समाचार पत्रों के सम्पादकों

और संवाददाताओं को भ्रष्टाचार के मामले निर्भीकता से प्रकाशित करने चाहिए। यह मामला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए भरतपुर का है। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि किस तरीके से संवाददाताओं की पिटाई हुई है। यह समाचार भरतपुर के पाक्षिक समाचार पत्र "दतबन्धु" में प्रकाशित हुआ है—

"भरतपुर से प्रकाशित पाक्षिक पत्र दत्तबन्धु के सम्पादक गणेश दत्तबन्धु, रैड इण्डिया के प्रतिनिधि राजेश गौड़, दैनिक आज की आवाज के जिला प्रतिनिधि रामकुमार शर्मा पर भूतपूर्व विधायक के सुपुत्रों तथा रमेश थानेदार के भाई सत्यकाम गुप्ता द्वारा अन्य असामाजिक गुन्डों के साथ मिल कर प्राणघातक हमले किए जा रहे हैं और भरतपुर की पुलिस तथा प्रशासन मौन बैठा है।"

श्रीमन, इतना ही नहीं, उन्होंने सामूहिक रूप से संवाददाताओं और जन-प्रतिनिधियों ने आई० जी,० डी० आई० जी० और वरिष्ट मंत्रियों तक सम्पर्क किया और प्रस्ताव पास किये कि यह निन्दनीय घटना हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इन भूतपूर्व लोगों, पूर्व के भूत और प्रेतों, इन पुलिस कर्मियों की वजह से कोई आज तक जांच नहीं हो पा रही है। सरकार तक बात पहुंची है लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। यह हाल है, यह है हमारे देश में अपराधों की स्थिति है।

श्रीमन्, जब संवाददाता अपने अखबारो में पुलिस के खिलाफ, सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तब इसी तरीके के जुल्म उन पर होते हैं। इसी प्रकार से जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो दलाली का काम नहीं करते हैं, जब वे आवाज उठाते हैं तो उनका जीवन भी इसी तरह से संकट में पड़ रहा है। लेकिन यह सरकार चुप बैठी हुई है।

कल जब मंत्री जी अपना भाषण पढ़ रहे थे तो मैं उनका भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कुछ हरिजनों के बारे में समस्याएं बताई, रिजर्वेशन के बारे में, महिलाओं के बारे में आप कुछ करने जा रहे हैं यह बताया। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ट्रिब्युनल बनाने की बात मंत्री जी ने कही। लेकिन जो अत्याचार और उत्पीड़न हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ? यह जो लूटखोरी, घूसखोरी हो रही है इसके बारे में कुछ करना चाहिए था। मेरा निवेदन है कि सेठी जी इस ओर ध्यान दें और बतलाएं कि आखिर इस तरह के अपराध क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। क्यों हरिजनों पर जुल्म हो रहे हैं, गरीब लोग क्यों सताए जा रहे हैं।

16.01 hrs.

(Dr. Rajendra Kumari Bajpai *in the chair*)

आर्थिक अपराध भी इस देश में चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। कई वित्तीय संस्थाएं और कारपोरेशन बने हैं और उनमें नौकरी देने के नाम पर देश के नौजवानों को ठगा जा रहा है। जनता को कई तरह के लालच देकर ठगा जा रहा है। एक मामला प्रकाश में आया है। कोई निकाला हुआ कर्मचारी ** है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश का मामला है। लखनऊ से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इस व्यक्ति ने बड़ी चालाकी की। इसने संस्था बनाने के लिए आई. ए. एस. और आई. पी. एस. लोगों से संपर्क किया। विज्ञानपुरी जो कि आई. पी. एस. अफसरों की कालोनी है वहां पर इसने दफ्तर और रिहाइश के लिए मकान लिया। मार्केट वैल्यू के हिसाब से वहां पर किराया 2000 रुपए है, इसने 5000 रुपए महीने में अधिकारियों से मकान लिया। उसके बाद फाइनांस कारपोरेशन खुला। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कई अखबारों में विज्ञापन निकाले गए और सूचित किया गया कि चपरासी, क्लर्क, फील्ड आफिसर, रीजनल आफि-

** Not-recorded.

सर, मैनेजर आदि के पद भरे जाने हैं। चपरासी के लिए 1000, बाबू के लिए 2000, फील्ड आफिसर के लिए 3000, और मैनेजर के लिए 5000 रुपए जमानत के रूप में जमा कराए गए। इसके अलावा चपरासी रखने के लिए एक हजार, बाबू के लिए दो हजार इसी तरह से और लोगों से भी नौकरी देने के लिए घूस के नाम पर भी काफी पैसा लिया गया। अखबारों में 300 लोगों की बात कही गई है, लेकिन मुझे जानकारी है कि कम से कम 500 लोगों से इसमें पैसा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र के लोग इसमें रखे गए हैं। करोड़ों रुपया इस व्यक्ति ने इकट्ठा कर लिया है। इन लोगों को नौकरी देने के बाद पासबुकें खुलवाने का काम सौंपा गया। जो कारपोरेशन के नाम से 200 रुपए जमा कराएगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य नाम लेकर एलीगेशन नहीं लगा सकते। नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री रामलाल राही : मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में पत्र भी लिखा है और ** जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे मिला भी हूं। इस मामले में कोई जांच नहीं हो रही है। मामला दबाया जा रहा है। वरिष्ठ आई. ए. एस अधिकारी जो एडीशनल आई जी रैंक के हैं, उनका वरदहस्त इस व्यक्ति पर है। उनकी साजिश से संस्था चलाई गई है।

SHRI BUTA SINGH : Sir he cannot name the officres. it should be expunged.

श्री रामलाल राही : करोड़ों रुपया डकारा गया है। इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। माननीय गृह मंत्री इसकी जांच करवाएं। इस तरह की फर्जी फाइनेंस संस्थाएं नहीं पनपनी चाहिए।

SHRI BUTA SINGH : Sir, it should not form part of the speech.

(*Interruptions*) It should not be recorded.

सभापति महोदया : माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं। नाम लेकर एलीगेशन नहीं लगाया जा सकता। नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा। कोई भी एलीगेशन लगाने के लिए एडवांस नोटिस देना होता है।

श्री रामलाल राही : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

सभापति महोदया : अब आपका समय समाप्त हुआ बैठिए।

श्री रामलाल राही : ठीक है, इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput) : Because the time is short, therefore, I will be short in my submission. The work on tribal development has not been done in full, much more should be done.

In the Constitutional provisions we find political, protective and developmental provisions for tribals only in 1974-75 a new concept has been evolved by the Government of India, at the Government of India level. But before that only the State Government had prepared the schemes for the development of the tribal areas as well as the region. Only in 1980, for the first time, component plan for the harijans has been adopted. The preparation of the tribal sub plan has been completed. But the component plan and the projects which have been prepared by the States have not been fully submitted. I would like to bring to the notice of the hon. Minister regarding the implementation of the different policies adopted by the Government when they consitituted the Central Co-ordination Committee. Has each and every ministry been discussed in detail-how to quantify the fund and how to earmark the fund by the State as well as how to chalk out the programme for the tribal area and its development ? The concept of the tribal sub plan, the flow of the tribal sub plan fund, has it in principle been adopted by the Centre as well as the States ? The State Sector outlay has been increased substantially. But there are some lacunae while earmarking

** Not-recorded.

the fund by the States also. The allocation has been increased, no doubt, but only by giving the fund in the Budget sub head. But the funds which has been earmarked is not for the tribal upliftment that is for the development of other sectors or for the development of the State. Therefore the money shouwn and spent by the States has been increased substantially.

The Central special assistance which has been fixed for the Scheduled Castes and the scheduled Tribes has also to be increased. The States which are poor have no adequate funds to provide for these schemes. They have to be provided directly by the Home Ministry to the projects on the Time of providing funds adopted by the Ministry of Agriculture in 1972. There was matching grant previously. But now the matching grant has been changed and the special central assistance scheme the new concept adopted by the Centre. Therefore the money should flow to the project directly from the Ministry of Home Affars. The insitiutional finance should be earmarked by the Ministry of Finance has to flow in the tribal sub plan area as well as the Harijan component plan. I want to say something for sub plan concept of the Minstry. Government has adopted the sub plan in principle. It means the plans in the State plans, plans in the Central Ministeries plan. But out of a number of minsteries and departments, very few ministries and departments have been earmarked the funds so far. But it is also meagre. In the Annual Report of the Ministry, they have to show the developmental measures taken by them and the achievements they have made in the various fields. Except the item on reservations for S. C. and S.T. they have not given the developmental measures that have been taken for the upliftment of the Scheduled Castes and Scherduled Tribes by the various agencies under the chapter of subplan and the special component plan which is very necessary.

Madam Chairman, a large number of polices are being adopted by the Government. The forest policy which has been adopted by the Government is not being implemented by the States. Now, the Government has proposed to bring an amendment to the Forest Act. They have already constituted two committees and these committees will go into the details and recommend how to bring the new type of legislation which may ultimately go against the interests of the tribals who are supposed to enjoy various forest rights.

In 1952, when the Forest Act was passed, it deprived the rights of the tribals and of giving them the compensation, they have been given some concessions. 1980 Act also provides for some concessions. Now, if the Government would like to bring a new type of legislation, I would humbly submit that it will definitely affect the interests of the tribals.

The personnel policy is also very important for the Government of India to bring a legislation to make the administation uniform in the tribal areas. It is not that it should be done on the basis of my personal view. It should be done on the basis of the Constitution as article 339 (2) empowers the Government of India to give directions to a State for the welfare of the Scheduled Tribes and article 275 (1) empowers the Government of India to sanction grants-in-aid and assistance to the ribal areas and set up administration. The Constitution also gives power to the Governor to set up any type of administration in the interest of the State which is suited for the tribal area. There will be no bar or objection either from parliament or the Assembly. If they are to serve the tribal people, they should adopt a singl-line administration. This type of administration has been recommended by the different committees constituted by the Government of India.

There is a need to review the investment policy and the special Central assistance which are being released by the Centre to the States—whether it is to be utilised by the Central agency for the Central schemes or by the State agencies for the State schemes. Recently, I have come across one instance where funds meant for different purposes have been utilised in a particular area.

Madam Chairman, the industrial policyis also very important. The establishment of big industries in the tribal areas will literally develop the tribal areas and the socio-economic conditions of the tribal people. But the persons who have been displaced due to the establishment of big projects are to be taken care of. Therefore, my humble suggestion is, the

interests of the displaced persons, the development of the displaced persons should not be the responsibslity of the State Government only or any other agency but that should be the main responsibility of the project authorities who have established the big industry there. The project authorities should make a comprehensive plan even in the project report so that the persons who have been displaced by the industry are re-settled comfortably.

Madan Chairman, last time we requested for the setting up of a new Department for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and I think, it is under the examination of the Government. Madam, we are demanding that there should be a new Ministry or new Department on the basis of recommendations of the Bhebar Commission of 1961. Subsequently, the Government has constituted a number of committees or commissions on the subject and they have also recommended on the same line. So, I urge upon the Government that it is the need of the hour to create a separate Department which will look into the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and take the over-all responsibility of implementing the Constitutional provisions as well as the new policies that are adopted by the State and the Centre so that all the schemes and programmes meant for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are fully implemented.

The shifting of responsiblity from the State to the Centre and from the Centre to the State should be stopped. Unless you stop this, the things will not improve. Therefore, the development of S.C. and S.T. should be included in cuncurrent list of the Constitution by bringing the amendment in the constitution.

Recently, the parliament secretariat has circulated a book which gives the responsibilities of various Ministries/Departments. Here I find, for the first time, the Ministry of Home Affairs has been given the responsibility of tribal welfare. They have been entrusted with this responsibility. I would like that all the Ministries/Departments should also include tribal welfare as well as Scheduled Caste welfare under their respective Ministries/ Departments by which they will implement the policies and programmes for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and, while they submit their Annual Reports, they will at least mention what they have done for SCST people during that year.

Another point that I would like to make is that the approach which was there earlier has been changed for the betterment and welfare of tribals. The attitude has been changed not only at the Central level but also at the State level and at the project level too. The allocations have been increased. But the targets which have been laid down have not been achieved. The achievements not only in terms of physical targets but also in terms of socil and economic level. We should know whether the tergets have been achieved or not. The approach to this ctibal welfare has been changed. I disagree with those who are saying that this Government has not done anything for the SCST people and that they are still living in the same conditions. They are blaming the Government. I do not agree with them. After our party has come to power, under the able leadership of the Prime Minister, the things have improved.

There was a Committee appointed in 1972. They have submitted the report and, on that basis, a new approach, a new strategy, has been adopted for the first time in the history of tribal development in India. In the year 1980 the S.C. Component plan was started. When the question of implementation comes, they say that these are the difficulaties and the defects in the implementation of various schemes and programmes. These things should be rectified. It is not correct to say that the Government of India or our party has done nothing for the welfare of tribal people.

The special Central assistance should be increased. A large number of tribal areas are there. The State Governments are not allocating adequate funds for the welfare of tribals and for the development of tribal areas. There are two approaches. When it was the welfare approach, the money allocated was meagre. When we adopted the upliftment and development approach, improving the conditions of tribal people and developing the tribal areas, naturally; the allocations were increased. In the new 20-point Economic Programme, there is point No. 7 which covers accelerated programme of tribal development. That means the Government is putting all its

emphasis on this programme from all angles.

Lastly, I would like to make one more point. Under article 338, there is a provision of appointing a Special Officer for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, etc. There has been a controvery going on in regard to that. The post is still lying vacant after the recruitment of the Commissioner for S.C. and and S.T. When the Janata Government brought forward a Bill for the amendment of Article 338 of the Constitution, that Bill lapsed for want of quorum. The Government of India had appointed a Commission for S.C. and S.T. by the resolution.

Therefore, Artcile 338 of the Constitutions should now be amended suitably.

Under Article 275 (1) of the Constitution, the Commission made a provision of Rs. 42 crores for strengthening of administration in the tribal areas, to provide this amount to the statesi.

The next Finance Commission should increase the amount for the purpose of development of tribal areas.

Articles 275 (1) and 339 of the Constitution are interlinked for administration and development of the tribal areas. On that basis, I urge upon the Government of India as well as the State Government to provide funds for the development of the tribal areas.

It is important to note that the amount for the development of the tribal areas will be granted from the Consolidated Fund of India. Once the Schemes are prepared by the States, the amount will flow to the tribal areas from the Consolidated Fund. The Second Finance Commission agreed to this point. The Seventh Finance Commission has already provided the amount.

In future, the Government of India should provide funds both for the development and administration of tribal areas in future plans.

With these words, I conclude my speech and I hope that more and more Schemes and programmes by the Ministry as well as by the Government of India would be formulated in future plans.

* SHRI C.CHINNASWAMY (Gobichettipalayam) : Madan Chairman, on behalf of my party the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, I wish to participate in the discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs and make a few suggestions.

At the outset I would like to refer to the language issue. Madam, Delhi is the capital of the country. The people speaking different languages are living here. Besides, all the foreign governments are represented here. In these Embassies many foreign nationals are working. It is really surprising that Delhi should have been included in the Hindi-speaking zone. Consequently, the NDMC notices, the DMC Bills, the DESU Bills are all coming in Hindi. The LIC premium notices and orders from the Delhi Administration are also in Hindi. Naturally the non-Hindi speaking people are facing the problem of trying to understand what these communications say. I request that Delhi should be taken away from Hindi-speaking zone and it should be constituted into an exclusively Hindi-English zone to be in conformity with its cosmopolitan status.

The people of Tamil Nadu are opposed to the imposition of Hindi and not to the language as such. In Madras, Avadi, Tiruchirappalli, Salem, Aravangadu, and Coimbatore, there are permanent Hindi-teaching centres sponsored by the Government of India.

In Tirunelveli, Tuticorin, Kalpakkam, Nagercoil and Virudunagar there are part-time Hindi teaching centres of the Central Government. They are being run successfully and they are popular with the people. But, the non-Hindi knowing staff of the Central Government are compelled to learn Hindi and become proficient before they can stake their claims for promotion. In some cases, for crossing the Efficiency Bar in the scale of pay, the knowledge of Hindi is compulsory. I have to condemn this kind o[1]

* The original speech was delivered in Tamil.

imposition of Hindi. I request that the relevant rules and regulations in this matter should be suitably modified so that the non-Hindi knowing people are not unnecessarily harassed.

The Centre has constituted the Sarkaria Commission to go into the question of vexed Centre-State relations. It is more than a fortnight now. Yet the terms of referrence of the Commission have not been specified. It is not merely the political relations between the States and the Centre but also the financial relations that are to be gone into. The Eighth Finance Commission is currently studying the financial relations between the States and the Centre. I suggest that there should be proper coordination between Sarkaria Commission and the Eighth Finance Commission. I would even suggest that some of the Members of the Finance Commission should be co-opted on the Sarkaria Commission.

Madam, the Police Act was enacted in 1861. The National Police Commission has made several constructive suggestions for the improved functioning of our Police Force. I suggest that the new comprehensive Bill as suggested by the Police Commission should be enacted as soon as possible. All the other recommendations of the Police Commission should be implemented by the Government.

In 1983-84 a sum of Rs. 7.5 crores has been provided for the modernisation of Police Forces in the country. This is a measly provision. At least a minimum of Rs. 1 crore should be given to each State for the modernisation of Police Force. The outmoded approach to the problems of the Police Force should be done away with.

Madam, the M.L.As in the Union Territories do not have voting rights in the Presidential Election. We are doing injustice to the people living in the Union Territories. I suggest that the Constitution must be amended suitably for giving voting rights to the M.L.As of Union Territories.

Shri A N Mulla, a senior Member of the Congress-I Party is the Chairman of Jail Reforms Committee, which has suggested many meaningful reforms in its Report. This report points out that as on 31.12. 1980 there were 1,59, 692 prisoners, out of whom 92, 276 were under-trial prisoners. The non-criminal lunatics uumber about 2077 and out of this 21 are women. The number of persons who are in Indian prisons for more than two years without trial number about 2471. You must have come across reports about the appalling conditions prevalent in our jails. The Report of the jail Reforms Committee should be examined by the Government speedily and the recommendations contained therein must be implemented. Expeditious steps should be taken to complete the trials of prisoners.

Article 46 of our Constitution adumbrates policies and programmes for the economic and socil upliftment of our brothers belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. But, the Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950 in para 3 prohibits those scheduled castes and scheduled tribes people who have converted to Christianity, Islam and Buddhism from enjoying the amenities being granted by the Government. After all their number would be just 2 crores and the annual expenditure would be just Rs. 10 crores if the amenities are extended to them also. I request the hon. Home Minister to look into this and do the needful.

Madam, the communal clashes in 1978 were just 230. In 1982 they have gone up to 474. Unfortunately the communal clashes are also exploited for political upmanship. The guilty go scot-free because of the loopholes in the law. Now the Government of India has constituted the Minorities Commission, I suggest that this Commission should be given legal status and statutory support so that such communal clashes are gone into by the Commission and the deterrent punishment awarded to the miscreants immediately. I understand that the Minorities Commission has not got even full membership so far. I request that the Home Minister should ensure that the full-fledged Minorities Commission becomes a statutory authority with mandatory powers to punish the guilty in the communal clashes.

In this background it becomes a serious problem when guns and ammunitions are stolen from armouries, as has been recently reported about the theft of guns and ammu-

nitions from Ferozepur and Shillong Armouries. If these lethal weapons fall in the hands of evtremists, then the innocent people will be the victims of their vandalism. I suggest that the Armouries must be given proper protection.

On pages 63 and 64 of the Home Ministry's report the amounts have been indicated as 'crores'. They should be only 'lakhs'. I suggest that necessary corrections may be carried out.

Before I conclude, I would say with all the force at my command that the law and order situation in Tamil Nadu is at its best under the leadership of my leader Puratchi Thalaivar Thiru M.G.R. It cannot be otherwise under the rule of Thiru M.G.R because he has dedicated himself to the good of the Tamil pcople. His commitment to the common weal has been affirmed by our hon. Prime Minister of India who visited Tamil Nadu last year. After her confabulations with the high officials of the Government of Tamil Nadu, she has unequivocally commended the performance of the State Government of Tamil Nadu, particularly with reference to the implementation of Plan programmes meant for the upliftment of the downtrodden in the State. I need not say that the politically motivated criticism of others about the functioning of the State Government is a cry of despondence and frustration.

With these words I conclude my speech thanking you for the opportunity given to me to participate in the devate.

प्रो० सत्यदेव सिंह : माननीया सभापति जी, मैं गृह विभाग की अनुदान की मांगों का हार्दिक समर्थन करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी आप राष्ट्रीय सरकार के गृह मन्त्री हैं। आप उस पद पर बैठे हैं जिस पर कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और आप की सरकार की नीति.....

श्री रामावतार शास्त्री : पं० गोविन्द वल्लभ पंत भी थे।

प्रो० सत्यदेव सिंह : वैसे तो श्री लाल बहादुर शास्त्री भी थे।

श्री रामावतार शास्त्री : उनको भी बोलिये, एक ही के लिये क्यों बोलते हैं?

श्री एम० सत्यनारायण राव : ज्ञानी जैल सिंह भी थे।

प्रो० सत्यदेव सिंह : मैं आप से न्याय की मांग करता हूं। हमारी सरकार की यह नीति है कि सबों को न्याय मिले और उसी न्याय के क्रम में मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी प्रकार का अन्याय किसी के प्रति भी न हो।

मण्डल आयोग के सम्बन्ध में माननीय श्री बलिराम जी भगत, माननीय श्री चन्द्रजीत यादव, माननीय श्री आर० पी० यादव, प्रो० डी० पी० यादव, माननीय श्री राम विलास पासवान जी के विचार सुनने का मुझे मौका मिला। यह मण्डल आयोग जनता पार्टी की देन है। जो वर्ग अपने को प्रभावित पाता है, उसी वर्ग के एक व्यक्ति को इसका न्यायाधीश बनाया गया। होना तो यह चाहिए था कि किसी सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व या वर्तमान न्यायाधीश को इस पद पर बिठाया जाता। तभी इस से न्याय की आशा की जा सकती थी। मेरी यह राय है कि इसकी रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि ये यादव बन्धु जो भगवान कृष्ण की सन्तान हैं, वे कैसे सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। गतवर्ष पटना में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे सभाध्यक्ष भी गये थे। श्री राम लखन जी यादव उसके स्वागताध्यक्ष थे। वे प्रबंधक भी थे। इनको सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कभी नहीं कहा जा सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव बन्धु किसी से भी पिछड़े हुए नहीं हैं—चाहे बौद्धिक, सामाजिक, शैक्षिक किसी भी दृष्टि से क्यों न लें। ये सभी दृष्टि से समुन्नत और शक्तिशाली हैं, प्रौढ़ हैं। इनकी शक्ति का प्रदर्शन तब होता है जबकि मतदान होता है। मतदान केन्द्र में ये किसी हरिजन को कभी भी नहीं जाने देते हैं। फिर मण्डल साहब तो

इतने बड़े जमींदार थे कि उनके सामने अन्य जातियों की बात तो छोड़िये, यादव जाति का भी कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता था। हमारे माननीय सदस्य श्री शास्त्री जी इसका अनुमोदन करेंगे। यह मैं मानता हूं कि यादवों को हटा दिया जाए क्योंकि वे किसी मायने में भी सामाजिक या अन्य दृष्टियों से पिछड़ हुए नहीं हैं। पिछड़े वर्ग में कुर्मी, चमार, कहार जो लोग हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं है। पिछड़े वर्ग के नाम पर केवल इनका नाम ही सामने होता है। मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं। वहां पर परसा विधान सभा क्षेत्र से किसी व्यक्ति को विधायक बनने का मौका नहीं मिलता है, वहां से केवल यादव ही चुन कर आता है। यादव बन्धुओं का बहुमत वहां है। वहां पर कुर्मी, हज्जाम बहुत बड़ी संख्या में हैं। लेकिन उनको मत देने के लिए जाने नहीं दिया जाता है। यह मैंने स्वयं देखा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मण्डल आयोग की रिपोर्ट को नये सिरे से देखा जाए और नये सिरे से इसकी जांच की जाए। हमारे यादव बन्धु सब तरह से सर्वांगीण अधिकार प्राप्त हैं। यादवों को पिछड़े वर्ग से हटाया जाए।

श्री आर० पी० यादव ने कहा कि पिछड़ वर्ग के लोग 85 प्रतिशत हैं। यह कैसे माना जाए। ये हरिजनों आदि का सामान्य मंच बनाते हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखें कि आजादी के बाद हरिजनों के साथ किसी ने अत्याचार किये हैं तो वे यादवों ने किये हैं और इन से सभी लोग आतंकित हो जाते हैं।

श्री बलिराम भगत ने बिहार में राजपूत, ब्राह्मण, घुमियार और कायस्थ आदि को 20 प्रतिशत माना है और कहा है कि इनको 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। मैं नहीं समझता कि किस आधार पर इन्होंने यह कहा है। इतने विवेकशील व्यक्ति ने किस आधार पर यह कहा है। कई ब्राह्मण ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है। ये लोग भिक्षाटन करते हैं और पूजापाठ करते हैं। जमींदारी और जागीरदारी खत्म हो जाने से अब भिक्षाटन ही इनका सहारा रह गया है। कायस्थ भी केवल कलम चलाने वाले हैं। रोजी नहीं तो रोजा वाली बात इनके साथ है। ऐसे लोगों को आरक्षण में स्थान नहीं दिया गया है और यादवों को आरक्षण में स्थान नहीं दिया गया है और यादवों को आरक्षण में स्थान दिया गया है यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

श्री बी० डी० सिंह : किसी एक जाति के बारे में आप इस तरह से नहीं कह सकते। यह आप गलत कर रहे हैं।

प्रो० सत्यदेव सिंह : मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आप पहले राव और रावत कहे जाते थे, अब सिंह कहे जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि भारतवर्ष की हर जाति सिंह कहलाए। लेकिन इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए।

श्री बी० डी० सिंह : किसी एक जाति को लेकर इस तरह से माननीय सदस्य कहे जा रहे हैं। इसको एक्सपंज कीजिए। मैं इसका विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि यादव जाति को उसमें न रखा जाए।

सभापति महोदया : एक ही जाति को लेकर इतनी बात करने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० सत्यदेव सिंह : मैं दूसरे प्वाइंट पर आ रहा हूं। लेकिन यादवों को इसमें से हटाया जाए।

श्री बी० डी० सिंह : जहां-जहां यादव शब्द का उपयोग किया गया है उसको एक्सपंज किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : माननीय सदस्य, आप कृपया एक जाति को लेकर न बोलें। इससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। दूसरे प्वाइंट पर बोलिए।

(व्यवधान)

प्रो० सत्यदेव सिंह : हरिजनों को पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाए। मैं इस बात का प्रबल समर्थक हूं।

सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री वी आर० अय्यर ने 11.4.83 के अमृत बाजार पत्रिका में सुझाव दिया है—

> "Women right's in the country were only in letters. Helpless women took to prostitution. Rapes were a daily featurer. Even in Police Stations women were molested. They got less wages than men. Womenfolk should make loud protests against these injustices."

अभी जिस प्रकार से प्रमिला जी ने कहा था कि महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत है। उनके साथ घोर अत्याचार किया जा रहा है। महिलाओं का स्थान समाज में महान होना चाहिए। भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है, जिसने रमणी की पूजा की है। हमारा कोई भी यज्ञ उसके सहयोग के अभाव में पूर्ण नहीं हाता है।

विश्व के अनेक राष्ट्रों में महिलाओं के लिए समान स्थान नहीं है लेकिन भारतीय प्रजातंत्र में बिना लिंग-भेद के समान अधिकार दिया गया है। इसलिए, मैं चाहूंगा कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। जैसा कि श्री अय्यर और आज श्रीमती दंडवते जी ने भी कहा है कि महिलाओं को 25 प्रतिशत स्थान मिलने चाहिए लेकिन, मैं चाहता हूं कि उनको तो और अधिक स्थान मिलने चाहिए। उनके साथ अत्याचार होता है। माननीय सभापति जी, मेरे पास अखबार की एक फोटो है जो कि 10 अप्रैल 1983, इन्डीयन नेशन में छपी है। इससे पता चलता है कि किस प्रकार कोडाइ विलेज मुजफ्फरपुर में पांच महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया जो श्राद्ध हैल्डिन अस्पताल में हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। मन्डल आयोग को रद्द कर नए सिरे से आयोग की स्थापना और जांच की जाए। आरक्षण का आधार जाति पर नहीं आर्थिक होना चाहिए। पिछड़े वर्ग के नाम पर अपने प्रभुत्व को सरकारी नौकरी में जमाकर प्रजातंत्र को समाप्त करने की साजिश है, उसको समाप्त किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को कहना चाहती हूं कि वे समय का ध्यान रखते हुए बोलें।

*SHRI BAJU BAN RIYAN (Tripura East): Madam Chairman, I will make my speech in Bengali. While speaking on the demands of the Ministry of Home Affairs, I will not touch upon detailed demands of this Ministry but will confine myself only to the Scheduled Castes and Tribes, the Tribes, the Tribals and the Harijans as my time very limited.

In the capitalist system prevailing in our country, the Tribals, the Scheduled Castes and the Harijans are the weakest sections. Because they are the weakest section, the Govcrnment of India is making efforts to improve their standard o: living. This I will readily admit. But the big question is, how much improvement has been effected in the standard of economic life of these weakest sections in the last 35 years of uninterrupted Congress rule. This Congress Government shows much concern for the Scheduled Castes/Tribes and the Tribals at the time of elections. But they refuse to recognise the protection and safeguads provided for these people in our Constitution. A Commission was constittuted for the SC/ST in July 1978 under the Chairmanship of Bhola Paswan Sastri, as required under article 338 of the Constitution. The first report submitted by this Commission is in my hand. In para 3.4 of Chapter III of this report dealing with 'Economic development of Scheduled

* The riginal speech was delivered in Bengali.

Castes and Scheduled Tribes, it has been stated—I have no time to read the full text of this chapter but I will quote briefly from this. It mentions about the extent of improvement effected in the standard of living of the tribals, the Harijans, SC/ST etc. in the decade 1961 to 1971: I quote from this;

> 3.4. "An idea of the deterioration in the economic condition of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes living in rural areas can be had from some comparative data of 1961 and 1971 Censuses quoted by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in his Report 1975-76and 1976-77.In 1971, 82.3% and 93.8%SC and ST workers respectively were engaged in the primary sector of economy (which includes workers engagin as cultivators,landlers labouress and ed mining, quarrying, livestock, forestry, hunting and Plantations, orchards and allied activities), 8.1% and 2.5% respectively were in the secondary sector (which includes workers engaged in honsehold industry, manufacturing other than household industry and constructions), and 9.4% and 3.9% respectively in the tertiary sector (which includes workers engaged in trade and commerce; transport, storage and communications and other services). It is signficant that during 1961-71 there had been a decline in the contribution of the secondary and tertiary sectors. The growth in the primary sector has actually resulted in an increase in the population of the landless labourers and a decline in the proportion of cultivators and no significant mobility from primary to other sectors of economy."

Therefore, I am trying to show that during the decade 1961 to 1971 the standard of living of the Harijans, Tribals etc. have considerably declined, whereas the number of landless labourers have shot up. Out of 1000 labourers the number of scheduled castes have increased from 345 to 518 and those of scheduled tribes have increased from 197 to 330. During the same period the number of small cultivators among the scheduled Castes and scheduled tribes declined from 378 to 279 and from 681 to 576 per thousand respectively. This shows that many small land owners beloning to SC/ ST and the Tribals lost ownership of their land during that period. But the funds allocated by the Government in the Sixth Five Year Plan for raising the standard of living of these poor people, is extremely meagre. Madam, in reply to unstarred question No. 5899 asked by Shri Ajoy Biswas in this House on 6.4.83, the Government has stated that the per capita allocation for SC/ST in the Central Sector is about Rs. 123.00 for 5 years. This is according to the census figures of 1971. If the figures of 1980 are taken into consideration, then the per head allocation will be much less. In the Sixth Five Year Plan out of the total allocation of Rs. 97000 crores for the entire population of the country, the amount allocated for the uptiftment of the Tribals is a meagre 650 crores. According to my calculations the per capita allocation in this respect comes to only Rs. 123. 00 for 5 years or roughly Rs. 24.60P per year. You admit that the Harijans and the Tribals are the weakest section and that you are trying to better their standard of living. But how can you achieve that with a per capita allocation of Rs. 24.60 per year, I fail to comprehend. If I am wrong in my above calculations. I will certainly expect the Government to correcnt my figures.

Madam, as the Congress party is running the Government at the Centre, similarly in some States opposition parties are also in power and running the Government there. For example in Tripura and in West Bengal the Left front is running the Government under the leadership of CPI (M). There they have taken cerain steps, within the framework of our coustitution, for the upliftment of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Tribals, Harijans etc. The former left front Government (1978-82) tried to extend the provisions of the 6th Schedule in Tripura with a view to raising the standard of living of these classes. But the Centre turned down their proposal. Therefore, the left front Government constituted the 'Tribal areas autonomous district Council' under 7th Schedule with 28 elected members. But this Council is having difficulties due to paucity of funds. The State Government is advancing whatever funds are possible from their meagre resources. They are not getting any Central assistance in this espect. I will request the Central Government to come

forward and assist this district Council with finances to protect the interests of the Tribal people of Tripura. In the very first session of the State Vidhan Sabha after the recent elections, a resolution was brought demanding the extension of the provisions of the Sixth schedule to Tripura also. At present the above provisions are applicaele to Assam only. That resolution was supported by all the parties like CPI (M), RSP, F.B.,C.P.I. AND BY all the mass organisations like G.M.P.,T.Y.E.,T.S.U., A.I.K.S., G.N.S., D.Y.F.I., S.F.I., C.I.T. U., etc. All of them are demading for the extension of the Sixth Schedule to Tripura through amendment of Article 244 of the Constitution, whereby central assistance will be available for the upliftment of the Tribals, Harijans SC/ ST etc.

16.50 hrs.

(Mr Deputy Speaker in the Chair)

At the time of the recent Vidhan Sabha elections in Tripura the Congress (I) Party also supported this demand. The Congress (I) made an electoral alliance with the Tribal Upa Jati samiti which is a splinter group and is responsible for all types of nefarious activities in the State including murders. The Congress allied themselves with this group to win the elections and hoped to come to power. They promised that if they were returned to Power, the Sixth Scheduled would be extended to Tripura also. But they could not come to power. of course with the help of the Yuva Samiti they captured a few seats where they previously had none. After winning a few seats with the help of the Yuva Samiti, when the above resolution the 6th schedule was debated in the Vidhan Sabna, the Congress (I(M.L.A.s remained silent. On this issue a friction developed between the Congress and the Yuva Samiti. The Yuva Samiti splintered into four groups and formed a new party called the Tripura Hill Peoples Party under the Chairmanship of Saralpada Jamatia, an... A. D. C. member. The Convener being Debabrata Kaloi. I want to place on record that the Congress party in Tripura with permission from the Centre and Shrimati Indira Gandhi is encouraging the secessionist party in Tripura.

SHRI MANORANJAN BHAKTA (Andaman and Nicobar Islands) : Sir, I rise to speak on the Home Ministry's grant. I am conscious of the shortage of time and I will be very brief in my statement. Tne Andaman and Nicobar Islands is a Union Territory. The Home Minstry has got a number of subjects in its jurisdiction and one subject is to provide good government to the Union Territories. My constituency Andaman and Nicobar Islands is also one of the Union Territories which is far away remote, isolated, and scattered island, and there at present we have got one Pradesh Council functioning for the last two years. The Government of India has been kind enough to upgrade the position of the Chief Commissioner by appointing one Lt. Governor. The present position is that the Pradesh Council is an Advisory body and it has no executive power but they sit in the Secretariat and handling the files they can record their views on the file without having any responsibility. At the same time, when they go to the people, since they are the representatives of the people, people think that they will be able to do something, fulfil their aspirations and when they come to Port Blair, the seat of the capital, there they are not in a position to do anything because they are only functioning in advisory capacity. That is why it is a very anomalous situation prevailing in that Island and that is why it is necessary that immediately Government of India should think about it and provide them a Legislature like the Union Territories of Arunachal Pradesh and Pondicherry. This is the urgent need of the Island.

One point you will understand that when in Delhi some officers are not wanted, some officers are involved in corrupt practices, then immediately the Government of India finds that the nice place for them is the Andaman and Nicobar Islands or the Lakshadweep. The people of those remote and isolated territories are suffering because those officers think that if they do not do any work and create more mischief, then they will be transferred to Delhi. That is why.. .. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY SPEAKER: In those days criminals used to be sent to Andaman and Nicobar Islands.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: My submission to the hon. Home Minister is that while selecting officers for such areas, they

should look into the integrity of such persons and then only such officers should be selected.

I would like to submit one more point that if the Government of India is not delegating more powers to the Lt. Governor or the Union Territory administration, for each and every thing, even for small matters, they have to run from pillar to post and the things are pending for years together. That is why my submission is that like the North-Eastern region as they have got one Cabinet Sub-Committee, the same type of Cabinet Sub-Committee—the same one or a separate one-should be applicable for the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep so that our problems could be sorted out easily.

There are certain problems of the wage-earners which are lying there for years together. For example the question of grant of Andaman Special Allowance to all irrespective of place of their recruitment or place of residence, this is pending with the Ministry of Home Affairs for a long time and I request the Home Minster with folded hands to take up this matter and sort it out immediately.

In the Andman and Delhi Civil Service, which is called a Running Civil Service and Running Police Service, though substantive appointments were issued in 1973, all these orders have been lying pending either at Port Blair or in the Ministry with the result the officers of Andaman and Nicobar are suffering. Some of them have retired, others have died, but the substantive appointments have not come. With folded hands I appeal to the hon. Minister to look into the matter, sort out all problems for the benefit of the staff working in Andaman and Nicobar islands.

I was carefully listening to the speech of the hon. Member from Tripura. Though law and order is a State subject, which is also the reply given to us when we raise it here, a recent judgment of the Supreme Court of India has struck down section 303 IPC regarding the imposition of penalties on the ground of the fundamental right of the citizen. But we must remember that safeguarding the fundamental rights of the citizens is a Constitutional obligation of the Central Government. Earlier, there were only Congress Governments through-out the country. Now some other Governments have come to power in different States. We find that in some of those States political murders and rape are going on. Two or three days back, one MLA of Tripura, Shri Parimal Saha was brutally murdered. It is a matter of serious concern to all of us that a State Government cannot provide security even for a legislator, not to speak of the common citizens. Therefore, the Central Government should have to think in what way it can provide safety and security to the lives of the citizens of the country, as enshrined in the Constitution. In this context, we should also take into account this judgment of the Supreme Court because, to my mind, it is an encroachment by the judiciary on the domain of the legislature. I hope this point will be looked into.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (खूंटी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा करते हुए मैं गृह मन्त्री जी का ध्यान विशेष रूप से दिलाऊंगा—इस समय बहुत से प्रान्तों में, खास तौर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसी हालत हो गई है कि वहां का जनजीवन दूभर हो गया है । रात को डाकुओं का डर रहता है और चौबीस घन्टे आप की पुलिस के आतंक का डर बना रहता है । बिहार की भी यही हालत है । प्रश्न उन घटनाओं को सुनाने का नहीं है, घटनाओं का तो अम्बार लगा हुआ है, मैं तो उदाहरण के लिये एक ही बात कहता हूं—मैं दावत देता हूं अपने किसी भी राज्य मन्त्री को जो गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित है, मेरे साथ भेज दीजिये और जिस थाने में कहिये वहां उन को डाकू करार दिला कर पुलिस से मिल कर उन का एन्काउन्टर करवा सकता हूं । पुलिस इस स्थिति पर इस समय पहुंच गई है । लोगों के जनजीवन की सुरक्षित करना सरकार का उत्तरदायित्व है । संविधान में जो गारन्टी दी गई है—जीवन की और सम्पत्ति की—उसकी रक्षा होनी चाहिये और आप के गृह मन्त्रालय पर उस का अधिक दायित्व है ।

मैं उन्हें एनकाउन्टर्स की घटनाय नहीं सुनाना चाहता हूं, लेकिन एक घटना बतलाता हूं—नैनीताल से लाकर बदायूं जिले में पिछले महीने एक नौजवान की हत्या की गई। टेलीग्राम दिये गये—एस० पी०, नैनीताल को, एस० पी० बदायूं को कि एक थानेदार द्वारा बदायूं जिले के कचला थाने में एक नौजवान को लाया गया, और कह दिया। उसका बाप आया, उसकी हत्या की और उसका भाई आया तो उसको जेल में बन्द कर दिया। सारी घटनाएं आपके सामने आई हैं, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। क्या यह इसी तरह से चलता रहेगा? क्या लोगों में इसी तरह से असुरक्षा बनी रहेगी? पुलिस के अधिकारों को आपको सीमित करना पड़ेगा। आपको पुलिस को सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी। आज जो पुलिस का छोटा कर्मचारी है, वह अपने को असुरक्षित समझता है। उसकी सर्विस कंडीशंस ऐसी हैं कि उसको 24 घन्टे काम करना पड़ता है। उसको कोई फायदा नहीं मिल पाता। जहां आपको इन छोटे कर्मचारियों को सुविधाएं देनी पड़ेंगी, वहां आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टीगेशन मशीनरी को आपको बाकी के पुलिस कामों से अलहिदा करना पड़ेगा। अगर यह अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपका भी एन्काउन्टर करवा सकता हूं। पुलिस वाला दस हजार रुपये लेगा और आपको डाकू लिख देगा। यह उत्तर प्रदेश की हालत है, मध्य प्रदेश की हालत है। यह बड़ी गंभीरता का प्रश्न है, आलोचना का प्रश्न नहीं है। इस पर सारे बलों को सोचना चाहिए। यह देश का प्रश्न है। आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसा अमेंडमेंट करें कि सारा काम तो पुलिस करे लेकिन तफतीस मजिस्टेट करे चाहे फर्स्ट क्लास करे या थर्ड क्लास मजिस्टेट करे। आप पुलिस की मशीनरी को अलहिदा कर दें और इन्वेस्टीगेशन की मशीनरी को अलहिदा कर दें।

दूसरी बात यह है कि 70 प्रतिशत क्राइम्स घट सकते हैं। मैंने पहले भी आपके सामने यह मामला रखा था कि जितने भी क्राइम्स होते हैं वे कारतूस से होते हैं। वे चाहे पिस्तौल, बन्दूक या रिवाल्वर किसी के भी कारतूस हों। ये कारतूस क्रिमिनल्स के पास कहां से आते हैं? ये जो लाएसेंस होल्डर हैं, वे डाकुओं और क्रिमिनल्स को सप्लाई करते हैं। आप यह व्यवस्था कर दें कि कोई भी कारतूस जो कि मार्किट में बिकेगा उसके पीछे नम्बर होगा। वह नम्बर बेचने वाला रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसको खरीदने वाले का नाम भी रजिस्टर में दर्ज करेगा। अगर किसी डाकू या क्रिमिनल से वह कारतूस पकड़ा जाए तो उस कारतूस को सप्लाई करने वाले का हमें फौरन पता चल जाएगा। इस से कोई किसी को कारतूस सप्लाई नहीं करेगा। आप समझियेगा कि गांवों में डकैतियां नहीं होंगी गांवों में लोग डंडे और लाठियों से मुकाबला करेंगे। इस से आपके 70 फीसदी क्राइम्स घट सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि विदेशों से जो कारतूस इम्पोर्ट होते हैं उनका क्या होगा। उन पर भी आप यह कंडीशन लगा सकते हैं।

तीसरी बात मैं मंडल आयोग के बारे में गृह मन्त्री जी से कहना चाहता हूं। आप पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, यह मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में आप से कहना चाहता हूं। आपको पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ फ्राड नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 340 के मुताबिक काका कालेलकर कमीशन की जो रिकमण्डेशंस आयी थीं उनको भी आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आप कहते हैं कि आपने उसकी सिफारिश को लागू कर दिया है। मण्डल आयोग की सिफारिशों को भी आप टालते जाते हैं, आप उन्हें भी रद्दी की टोकरी में डालना चाहते हैं। इस तरह से आप पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रेरित कर रहें हैं कि वे भी आन्दोलन का तरीका अपनाएं। इसके द्वारा आपके फिशरमैन, मल्लाह, झींवर, कहार, हज्जाम, मांझी जिनको कि आपने आज तक कोई फायदा नहीं दिया है, वे भी अपने को जन-

जाति की सूची में सम्मिलित कराने का प्रयास करेंगे। उस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है।

इतना कहता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री दलबीर सिंह (शहडोल) : मैं सदन में प्रस्तुत गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में ही कहना चाहूंगा।

हर सेसन में यह मांग आती है कि आई० टी० डी० पी० या सब कम्पोनेंट प्लान जिसको कि एक डिवीजन देखता है, उसके लिए होम मिनिस्ट्री में एक डिपाटमेंट होना चाहिए। यह मेरी मांग आज भी है।

दूसरी चीज यह है कि मैं रिपोर्ट को पढ़ रहा था। इसमें आई० टी० डी० पी० और सब कम्पोनेंट प्लान के लिए केन्द्रीय शासन द्वारा केवल 680 करोड़ रुपया 1982-83 में दिया गया है। यह रुपया बहुत कम है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। इसमें बतलाया गया है कि 181 जगहों पर आई० टी० डी० पी० प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें से 62 प्रोजेक्ट्स मध्यप्रदेश में हैं जिनमें से 38 मेजर, 8 मिडियम और 16 माइनर प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या सब से ज्यादा है। अभी मैं स्टेट का रिपोर्ट देख रहा था। उस रिपोर्ट में आया है कि इन प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत 15 लाख आदिवासी आते हैं जिनमें से 12 लाख आदिवासी वहां पर गरीबी की रेखा के नीचे हैं, गरीब लोग हैं। केन्द्रीय सहायता का राज्यों में सही उपयोग हो रहा है या नहीं इसको देखा जाना चाहिए। कंपोनेंट प्लान की तो कई जिलों में भी नहीं है कि यह प्लान क्या है इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है।

बस्तर के बारे में पहले भी मैंने इस सदन में ध्यान आकृष्ट किया था। पिछली बार भी सूचना और प्रसारण मंत्री जी ने कहा था कि यह सुनी सुनाई बात है कि बी० बी० सी० द्वारा बस्तर में फिल्मांकन किया गया है और विदेशों में ब्लू फिल्म प्रदर्शित की जा रही है। 10 मई 1983 को पश्चिम जर्मनी की टीम घोटुल में गई। यह मामला प्रकाश में आया है। क्या इस टीम को केन्द्र सरकार ने परमिट किया था या राज्य शासन ने इसको परमीशन दी थी। यह जांच का विषय है और इसकी जांच की जानी चाहिए। आदिवासी संस्था "घोटुल" एक सामाजिक संस्था है। यह पवित्र संस्था है। इस तरह से आदिवासियों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इस सारे मामले की जांच की जानी चाहिए। पिछले मामले की जांच हुई उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। माननीय तिवारी जी ने भी इसी सदन में प्रश्न उठाया था मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी स्वाभिमानी लोग हैं। इस तरह से उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। क्या वे नारेबाजी करना नहीं जानते या स्लोगन लगाना नहीं जानते ? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि केन्द्र शासन उनको संरक्षण दे। आदिवासी और भोले भाले लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इस पश्चिम जर्मनी की टीम के बारे में पूरी जांच होना चाहिए। मेरा माननीय सेठी जी से निवेदन है कि वे अपने स्तर पर इसकी जांच करवाएं और तथ्यों का पता लगाएं।

बस्तर में सरगुजा, मण्डला और रायगढ़ जिले हैं। इन जिलों में आदिवासी और गरीब लोग—रहते हैं। इनकी गरीबी और भोलेपन का फायदा उठाकर यहां पर बड़े पैमाने पर कन्वर्शन हो रहा है। वहां के लोग यह भी नहीं जानते कि हमारा धर्म कौन सा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए शीघ्र कार्यवाही की जाए और कन्वर्शन पर रोक लगाई जाए।

इसी तरह से फारेस्ट पालिसी राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में रखी गई है। आदिवासी लोग वर्षों से फारेस्ट विलेजेज में रह

रहे हैं। उनको हटाया जा रहा है। उनमें एक अनिश्चितता की स्थिति है कि कहां जाएं। इसके लिए जो टास्क फोर्स बनी है उसमें जन प्रतिनिधियों को नहीं रखा गया है। टास्क फोर्स के सामने वहां की दिक्कतों को कौन प्रस्तुत करेगा। इसलिए जन प्रतिनिधियों को इसमें रखा जाना चाहिए। बस्तर में फारेस्ट प्रोड्यूज बहुत ज्यादा होता है और आदिवासी लोग उसी पर निर्भर रहते हैं। उसी से अपना जीवन बसर करते हैं। हालांकि यह कृषि विभाग का मामला है लेकिन इसमें होम डिपार्टमेंट का उत्तर दायित्व भी आ जाता है। आज जो फारेस्ट पालिसी बन रही है उससे आदिवासी लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस ओर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

उत्तरप्रदेश सरकार ने जो भारत सरकार को शेड्यूलकास्ट की लिस्ट भेजी है, उसमें ट्राइब्स को भी शामिल किया गया है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसको भी आप देखें।

समय नहीं है इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं। माननीय सेठी जी कुशल प्रशासक हैं। उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे सारी स्थिति को देखें।

वेंकटसुब्बैया जी ने कल कह ही दिया है कि हमने बैकलाग पूरा कर दिया है। फर्स्ट, सेकण्ड और थर्ड केटेगरी सर्विसेस में जो लोग रह गए थे उनका सारा कोटा पूरा कर दिया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए है उन पर माननीय सेठी जी ध्यान दें।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जिन बातों का जिक्र हो चुका है उनका मैं यहां पर जिक्र नहीं करूंगा। मान्यवर, बिहार से तीन विधेयक अभी राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए यहां पड़े हुए हैं। एक के बारे में काफी चर्चा हुई है "प्रेस विधेयक"। इसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा सिवाय इसके कि अभी यह कानून बंध नहीं है। इसीलिए या तो राष्ट्रपति इससे इन्कार कर दें या राज्य का विधान सभा इसको वापिस ले। वह कार्यवाही हो जानी चाहिए। उससे अधिक खतरनाक है दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन जो बिहार सरकार ने सिर्फ बिहार के लिए किया है। वह संहिता जो इस सदन ने और राज्य सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकृत की थी और उसकी प्रवर समिति थी जिसका मैं भी सदस्य था, सर्वसम्मति से स्वीकृत की थी। बिहार ने राष्ट्रीय नीति से अलग न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों में विभाजन था, उसे खत्म करने की योजना बनायी है। छ: महीने की सजा जिसमें 80 प्रतिशत मुकदमे आते हैं, वह कार्यपालिका करने के लिए तय किया है और बिना चार्ज-शीट के किसी आदमी को 6 महीने तक जेल में रखा जाए जबकि इस सदन ने दो महीने की अवधि रखी थी। जनता पार्टी के नाम पर जो सरकार आई उसने उसको ड्योढ़ा कर दिया और बिहार की कांग्रेस सरकार महा जनता बन गई, उसने तीन को छ: कर दिया। इसलिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्रीय नीति के प्रतिकूल एक नया विधेयक पास हुआ है जिसमें जमीदारी प्रथा वापिस लायी जा रही है। 1950 ई० से लेकर, जमशेदपुर और उसके अगल-बगल में जो जमीनों के मालिक थे···

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप राम : लॉ एंड आर्डर को सुधारने के लिए बिहार सरकार इस प्रकार का विधेयक लायी है।

श्री भोगेन्द्र झा : अगर उद्योग की बड़ी फिक्र है तो टीसको का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए और टाटा के चेयरमैन को सेल का अध्यक्ष बना लिया जाए या हमारे सदस्य की जगह पर उनको लोक सभा में रख लिया जाए। आप कहते हैं कि कानून को कड़ाई से लागू कर रहे

हैं। कानून की हालत यह है कि कल गोपालगंज के जिला-समाहर्त्ता की हत्या हो गई। वे दिन में एक बजे भोजन के लिए निकले और बम फेंक कर उनकी हत्या कर दी गई। सरकार ने दो लाख रुपए का एलान किया है, इससे जान तो वापिस नहीं आ सकती। बिहार की कार्य-पालिका कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों में अक्षम है। वह न्यायपालिका के पास जायेगी और टेलीफोन पर ही मुकदमों का फैसला हो जायेगा। इस प्रकार का वातावरण होता चला जा रहा है।

खुतबे और तकमा दो अछूत जातियां हैं। गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वह अछूत नहीं हैं। जो अधिकारी ऐसा कहते हैं उनको मालूल होना चाहिए कि उन जातियों को जन्म से ही विद्या में, घर में, पिछड़ा और अछूत बनाकर रखा जाता है। इसलिए, उनको हरिजनों की श्रेणी में शामिल करना आवश्यक है। मण्डल आयोग के विषय मे इतना ही कहना है कि आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए आरक्षण आवश्यक है। जिस तरह से बिहार में कर्पूरी ठाकुर के मुख्य मंत्रित्व काल में आर्थिक समता के आधार पर किया गया उसे गृह मंत्री देखें और उसी के अनुकूल देश भर में करें। जाति के आधार पर करने से जो पिछड़े और निर्धन हैं, वे छूट जाते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। हिन्दी हमारी राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा है। इसलिए सन्थली, नेपाली, मैथिली, और भोजपुरी आदि को भी शामिल किया जाए।

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे गृह मंत्रालय की मांगों पर बोलने का मौका दिया। मुझे लम्बी-चौड़ी बात नहीं करनी है। सदन में बहुत सी बातें की गई हैं। मैं एक बार बैकवर्ड क्लोसेज कमीशन का मेम्बर था। उसकी रिपोर्ट क्या है, यह एक अलग बात है। आर्टिकिल्स 333, 339, 340 की जरा फ्रेजियालोजो पढ़ ली जाय जिसका साफ मतलब है कि शैड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफैयर के के लिये 10 साल बाद कमीशन स्थापित हो सकता है, कमीशन नियुक्त करने का प्रोवीजन है, लेकिन वह तो आपने स्थापित नहीं किया। और जहां आवश्यक नहीं था क्योंकि काका कालेलकर कमीशन पहले बन चुका था उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी, उसके बावजूद भी जनता पार्टी सरकार ने मण्डल कमीशन नियुक्त कर दिया। माननीय भोला पासवान शास्त्री की अध्यक्षता में कमीशन बनाया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि आर्टिकिल 339 में स्पेशल आफीसर का प्रावधान है। मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

> "The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the comencement of this constitution by order appoint a commission to report on the administration of the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States."

यह तो लिखा हुआ है आदिवासियों के लिये लेकिन और उनके लिये कोई कमीशन नहीं बना। बैकवर्ड क्लासेज के लिये कमीशन बना दिया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

अब मैं वह आर्टिकिल पढ़ कर आपको सुनाता हूं जिसके अनुसार मण्डल कमीशन बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।

> "340 (1) The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educattonally backward classes..."

इस बारे में पहले ही कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी। और उपाध्यक्ष जी, आप दक्षिण से आते हैं, आपको मालूम होगा कि वहां पर सरकार के ऐग्जीक्यूटिव आदेश से

बैकवर्ड क्लासेज को जो कुछ मिला है उसके बारे में किसी को कोई एतराज नहीं है। परन्तु इस कमीशन की स्थापित करने से एक उलझन पैदा हो गई है। एक तरफ आरक्षण विरोधी ऐजीटेशन चल रहा है कि हरिजनों और आदिवासियों के अधिकार वापस लेने चाहिये और दूसरी तरफ यह ऐजीटेशन चल रहा है कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो।

अब 7,8 साल बाद आप सभी रिजर्वेशन बन्द करेंगे, हमारी सर्विसेज को बन्द करेंगे और फिर एक तरफ कहते हैं कि सिफारिशों को लागू कर के उन्हें रिजर्वेशन दो। तो यह दोनों बातें सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन क्यों नहीं नियुक्त किया।

ट्राइबल डैवलपमेंट के बारे में जो मुझ से पूर्व वक्ताओं ने कहा उसको क्यों नहीं माना जाता है? आदिवासियों के विकास के लिये ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत जो रुपया दिया जाता है उसका दुरुपयोग क्यों हो रहा है? इसलिये या तो आप अलग से मन्त्रालय बनाइये, नहीं तो रुपया देना बन्द कर दो।

आज 300, 400 जातियां आदिवासी हैं और एक बटे पांच उनका पौपुलेशन है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं क्या आपने कोई मंत्री बनाया? मैं विरोधी दलों से भी पूछना चाहता हूं कि जो आपने अपनी पार्टीज की स्टेट कमेटियां बनायी हैं, या कांग्रेस (आई) ने जो कमेटियां बनायी हैं जिनमें आपने आदिवासी और हरिजन सदस्यों को तो रखा है लेकिन क्या उनमें से आपने किसी को प्रेसीडेंट या सेक्रेटरी बनाया है? आज अधिकांश आदिवासी लोग सब-ह्यूमन लाइफ लीड कर रहे हैं। उनका जीवन बहुत ही दुखमय है।"

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन): इनको आप अपनी बात पूरी तो कह लेने दीजिये।

श्री भीखा भाई: मैं जानना चाहता हूं कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में आदिवसियों में से कितने लोगों को लिया है? कितने मिनिस्टर बनाये हैं?

Interruptions

Mr. DEPUTEY SPEAKER: The Home Minister has got to reply at 5.30 P.M. I think, I will have to ask the Home Minister to reply if everyone of you want to speak without my permission. The discussion has gone on for more than 15 hours. 12 hours were allotted by the B. A. C. We are now in the 15th hour. You are still not satisfied.

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हरिजन आदिवासियों के डेवलपमेन्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी गृह मन्त्रालय के ऊपर है। मैं विशेष तौर पर शिक्षा के संबंध में यहां पर कहना चाहता हूं कि आज आदिवासियों की क्या दशा है। 1971 की जनगणना के अनुसार देश में कुल जनजातीय आबादी की साक्षरता की प्रतिशत के मुकाबले मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता निम्न प्रकार थी :

	1971		
भारत	व्यक्ति	पुरुष	महिला
(क) सामान्य	29.45	39.45	18.69
(ख) अनुसूचित जनजातियां	15.72	22.57	7.87
मध्य प्रदेश			
(क) सामान्य	22.14	32.70	10.87
(ख) अनुसूचित जनजातियां	7.62	13.05	2.18

यदि इसी प्रकार की रफ्तार रही तो हरिजन आदिवासियों को उठाने में कम से कम सौ साल लगेंगे। हमारा रिजर्वेशन सिर्फ 7-8 साल और बचा है। अगर इस अवधि में काम नहीं हुआ तो हो सकता है इस सदन को यह रेजोल्यूशन पास करना पड़े कि यह रिजर्वेशन कम से कम सौ साल तक और जारी रखा जाए। आज दस परसेन्ट गावों में स्कूल ही नहीं है फिर वहां पर

शिक्षा का क्या प्रबन्ध हो सकता है यदि वास्तव में आदिवासियों को भी आप ऊपर लाना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको इंग्लिश सेन्ट्रल स्कूल खोलने पड़ेंगे ताकि आदिवासियों के बच्चे भी आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में पहुंच सकें ।

जहां तक कांपोनेन्ट प्लान की बात है, भारत सरकार की ओर से पैसा दिया जाता है लेकिन राज्य सरकारें उस पैसे को यूटिलाइज नहीं करती हैं और इस प्रकार से वह पैसा लैप्स हो जाता है । मैं चाहता हूं कि यह पैसा लैप्स न होने पाए । आदिवासी गरीब की रेखा से भी नीचे आते हैं । झोपड़ियों में वे रहते हैं, उनके पास एक टाइम्स भी खाने के लिए भोजन नहीं और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं । क्यों नहीं उन लोगों की मदद की जाती है ? किसी भी हालत में वह पैसा लैप्स नहीं होना चाहिए ।

आप यातायात के लिए परमिट्स और ड्राइविंग लाइसेन्स इश्यु करते हैं । आप दिल्ली से नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन टैक्सी पर जायें और यदि आपके पास आधे घन्टे का समय न हो तो आप ट्रेन नहीं पकड़ पायेंगे । मेरी कांस्टीटुएन्सी में दिनांक 29-3-83 को घुलैंडी के दिन रतलाम नगर के पास जामण पाटली में एक भयंकर ट्रक दुर्घटना हुई जिसमें 32 व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा । आपको ड्राइविंग लाइसेन्स के ऊपर भी कुछ कन्ट्रोल करना होगा ताकि इस प्रकार के जानलेवा एक्सीडेन्ट्स को रोका जा सके ।

इसके अतिक्ति मुझे मन्त्री महोदय की जानकारी में लाना है कि मेरी कांस्टीटुएन्सी में डूगरा में कमजी भील को पुलिस ने जिन्दा ही जला दिया । इस प्रकार की जो घटनायें आदिवासी क्षेत्रों में होती है उनकी सी० बी० आई० के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए । आज आदिवासी एरियाज में जो पुलिस है वह सुरक्षा के बजाए आदिवासियों के एक समस्या बन गई है । पुलिस को आता देखकर वे अपना काम काज छोड़ कर भाग जाते हैं । मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्रों में अच्छे पुलिस वालों को तैनात किया जाए तभी आदिवासियों का कुछ उत्थान हो सकेगा ।

मैं आपका और अधिक समय नहीं लेना चाहता । आपने जो समय मुझे दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे आदिवासियों के लिए अधिक से अधिक पैसा खर्च करें ताकि उनका भी उत्थान हो सके और उनमें भी जागृति आ सके । इन्दिरा जी के नेतृत्व में वे लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे नहीं रहना चाहते । इन शब्दों के साथ मैं होम मिनिस्ट्री की मांगों का समर्थन करता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the Minister will reply.

SHRI UTTAM RATHOD (Hingoli) : Those who have not been allowed to speak must be allowed to put questions at least.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is allright. It is not proper. The time allotted to each party has been exhausted. From yesterday the Minister was to reply. But I was giving chances to Members.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will give you more time on some other Demands, even 25 minutes. Now the Minister will reply.

SHRI RAMAVATAR SHARTRI (Patna) : You had assured me that you would allow me to say something about freedom fighters.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is allrigth. I have allowed Mr. Bhogendra Jha. Now the Minister will reply. We have taken 16 hours' Twelue hours discussion has gone upto 16 hours. Now the Minister will reply. All of you will kindly cooperate.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : You had assured me.

MR. DEPTY-SPEAKER : You can ask afterwards. This is the trouble with elde,

gentlemen. The younger Members are agreed...

SHRI P.C. SETHI : Mr. Deputy-Speaker, Sir, as many as 39 hon. Members...

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : This is wrong.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Your Party's time is over.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : This is wrong. You frankly say that you will not allow. Why do you assure that you will allow ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Bhogendra Jha spoke.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I am not responsible for that. You had told me that you would allow me to say something about freedom fighters.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is allright. Please do not record whatever he says.

SHRI RAMVATAR SHASITRI :**

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is left to you. You can have your own impression about anybody. It will not affect me. I have done justice to all the Members.

SHRI P.C. SETHI : As many as 39 hon. Members of this House have participated in this debate and have made useful contributions and suggestions for which I am thankful to them. It will be difficult for me to take the name of each and every hon. Member who has spoken here, bet some of the questions which have been asked by particular hon. Members, I shall try to meet.

I am also aware of the fact that my two clleagues, Mr. Venkatasubbaiah and Mr. Laskar, have covered some points about this Ministry and, therefore, I would not like to take the time of the House dwelling on those points again except making a brief reference to some of the important points.

As far as the Assam and Punjab situations are concerned, I would like to speak on them first.

As far as the recurrence of sporadic acts of violence in some parts of Assam is concerned, this is a matter of deep concern to this House, to the Government and to the whole country as such. When all efforts are being made to restore normalcy and render relief to the affected victims, such recrudescence of violence gives a setback to the delicate process of normalising the situation. The State Government have taken immediate steps to bring the situation under control ; wherever violence has been reported, reinforcements have been rushed to the affected areas and patrolling intensified. In all, 83 police stations have been declared as disturbed areas and the Chief Minister is periodically reviewing the situation. In spite of the fact that the Central paramilitary forces and other forces were deputed to Assam only for a short duration, they have not yet been withdrawn and we do not propose to withdraw them till complete normalcy is restored there.

I would like to clear one point. It has been made out in the foreign press as well as in some sections of the society in India that this carnage in Assam is totally communal.

I would like to dispel this misunderstanding. I would like to say that it was religious, linguistic and people from all sections and communities were involved. Of course, the number of Muslims who have been killed is certainly more. But Bengalis have been killed ; Assamese have been killed ; Nepalese have been killed ; tribals have been kille ; Biharis have been killed. The imperative need of the hour is to bring about a climate of goodwill and amity so that all people irrespective of caste, creed and religion, can live in peace and tranqulity and follow normal avocations.

There were more than three lakhs twenty-five thousand refugees in the camps. Now I am happy to report that more than one

**Not recorded,

lakh forty thousand have returned back. 171 police pickets have been opened up. They are looking to the needs of two lakhs of people.

Sometimes there are frequent reports of relief measures not being adeqbuate there. That is being looked into. Constantly the State Government is being reminded. The Chief Minister is himself looking now into relief work. Not only the local police and the officer are being involved in this but some of the Central officers have been also deputed for this purpose.

What is required at present is universal condemnation of violence in no uncertain terms. Violence has no place in a democracy and whatever grievances a section of people may have cannot be allowed to be exploited to be exploited to the extent that it threatens the unity of the country.

Sir, I sorry to say this. Some of the parties, particularly the BJP and its leaders have visited Assam. We have no objection to their visits. But the utterances which they have given there have further flared up the situation and have complicated the situation.

(*Interruptions*)

I have got the tape-recorded speech of Mr Atal Bihari Vajpayee...

श्री सूरज भान (अम्बाला) : हाउस में सुनवाइये । श्री अब्दुल गनी खां चौधरी की स्पीच भी हाउस में सुनवाइये ।

एक माननीय सदस्य : प्राइम मिनिस्टर की भी सुनवाइये ।

SHRI P.C. SETHI: As far as police pickets are concerned, 171 picket posts have been set up now.

As far as the refugees who have crossed over to Arunachal Pradesh is concerned, out of thirty four thousand refugees who have crossed over to Assam, barring 400, all have returned back and they are now rehabilitatedthere. The Assem Government is looking after them. There are about twenty-five thousand refugees and some ten thousand old refugees in Bengal. All efforts are being made to persuade them to return to Assam. Not only the officers but the two Assam Ministers have visited them and we have given them all assurance that when they came back, all protection will be provided to them.

As far as the West Bengal Government is concerned, we are thankful to them that they are assisting them. We have promised them that all the expenses that they incur for the refugees who have crossed over to West Bengal from Assam will be given from here and there will be no complication in this. (*Interruptions*) Sir, it is true that the development of not only Assam but the entire North Eastern region has lagged beh nd. Therefore Government are keenly interested in the accelerated development of Assam and that is why the outlay of Rs. 291 crores has been approved for 1983-84 which is 22% over and above the previous year's outlay. Apart from this there are other things which are being carried out. Now a new bridge near Jogigopa is being constructed and the cost of the bridge is going to be more than about eighty crores. And over and above that, some new railway lines connecting Gauhti are being given there. Some paper mills and cement mills are also coming up there. In this connection, I would also like to reiterate and make it very clear that there has been off and on demand for the dissolution of the Assembly and some of the Hon'ble Members of the Opposition have even approached the President and requested him to dissolve the Assembly and remove the Assam Government. We have no intention to do so. The Assam Government is duly elected and it is bound to remain in position and I am sure that they would certainly retrieve the position there.

As far as the Assam situation is concerned it has been also suggested that negotiations should be started there. But it has been suggested by some hon. Members that the same position should not be given to AASU and AGSP. I think Mr. Sontosh Mohan Dev made the position clear. Whenever we start the talks, we will have to involve all the concerned including the AASU and the AGSP. At present, we are

concentrating on two important issues. One is to look after the border security more intensively and to do something so that further immigration from Bangladesh is totaly stopped and secondly the Government has announced that from 1971 onwards, the process of detection and deportation will start and therefore this process has to be adopted and the Tribunals are to be appointed. As far as the enquiry is concerned, a high level enquiry has been ordered and soon the names of the persons who would go into the Enquiry will be announced.

As far as the foreigners issue is concerned, we want to make these Tribunals very wide based practically for every constituency we want to have a Tribunal and at the same time we would also issue the guidelines so that frivelous applications are not received or entertained by these Tribunals. As far as the personnel of these Tribunals are concerned, I would like to assure the hon. Members that we would appoint the Chairman of this Commission from outside Assam so that an empartial enquiry could be conducted into the whole matter. This is after all a Constitutional method and we cannot throw out all those without the legal process, who are considered to be foreigners.

Mr. Chandrajit Yadav, has made a point about the foreigners issue. For that purpose, a proper note has been sent to all the Embassies and some delegations of hon. Members, particularly, the Muslim MPs and and other Members are being sent from here in order to state the situation. Already Mr. Bahrul Islam has left the country for some countries to be visited.

श्री राम विलास पासवान : कि बात के लिए श्री वहरुल इसलाम को भेज दिया ?

SHRI P.C. SETHI : In order to clarify the position with regard to Assam, Now Mr. Chitta Basu has referred to the menacing increase in the activities of the divisive and separatist forces in different parts of the country, as is evident in Assam and Punjab.

We are also seized of this problem. As I have said, we are trying to tackle both these problems in a very cool and calculated manner.

As far as Punjab is concerned, although we had long talks in which the opposition was also involved, and we were almost at a point of a settlement, unfortunately the Akali Dal leaders moved out of the talks, and we could not finally decide.

As far as the religious demands are concerned, they have been conceded by the Government. We are in the process of consulting the Gurdwaras, and all those Gurdwaras which are willing to come under this Act, will be covered by this. As far as the relay is concerned, relay arrangements have been made for 1-1/2 hours in the morning, and half-an hour in the evening. But they are demanding some more time; and we have asked the Ministry of Information and Broadcasting to go into this.

PROF N. G. RANGA (Guntur) : Even now, are the Akalis free to come and have a dialogue with the Government?

SHRI P.C. SETHI: I am coming to that. As far as further talks with Akalis is concerned,if the Akali leaders do not send a second class team, but the top leadership comes here for talks, we are certainlyprepared to talk to them, so that they can talk to the authorities and clinch the issue. Otherwies also, we are also thinking of going into the question of water dispute; and we would certainly look into this.

With regard to the north-eastern area, I would like to say that in the north-eastern areas, as compared to Rs. 872 average per capita outlay in other States UTs, now Rs 1393 per capita outlay has been allotted there. The Loktak hydel project in Manipur is being commissioned during this year. The first phase of Kopili hydel project in Assam is likely to be commissioned. A mini cement plant in Tezu, Arunachal Pradesh will be commissioned soon. A North-East Regional Agricultural Marketing corporation has already been formed, under the aegis of the North Eastern council. Broad Gauge line upto Gauhati and certain other areas, particularly upto Gauhati is likely to be completed by 1984.

Six new railway lines are being constructed in order to bring all States and Union Territories on the railway map of the country. A road bridge, as I have said before, over Brahmaputra at Tezpur is under construction. Two large paper mills are being set up one in Nowgong and the other in the Cachar district, with a capacity of I lakh tonnes, and a capital cost of Rs. 232 crores. New industries are being set up.

Mr Niren Ghosh made a point about Tripura. It was that just before the elections, we declared certain areas, a very small portion or strech of land as a disturbed area. At that time, a fear was expressed by no less a person than the Chief Minister himself, that this wes a prelude to not having elections in Tripura. But we assured him that we were not going to come in the way of elections and that the elections would be held as scheduled. And elections were held, and the same party has come to power. We wish them well, and we would try to give them all necessary help, which isrequired from here, (*Interurptions*)

I will come to Centre state relations.

As far as communal harmony is concerned, I certainly agree with hon. Members that whatever might have been the Annual Report-which is an annual exercise-it is a fact that commual harmony is being disturbe and communal incidents are on the increase. The Centre has been in constant touch with the State Governments who have been advised from time to time to streamline their administrative machinery inorder to meet the challenges of the communal forces. In this connection, executive guideines have been given, a list of the communal sensitive areas and districts has been given to them and now instructions have also gone to all the States that there should be a restructuring of the police; their training should be done in a manner so that they are weel-oriented and they are more responsive to Public demand. It has also been said that there should be representative of the cross-section of society. I am glad to report that many of the State Governments have accepted this and they are going to implement this.

श्री राम विलास पासवान : ज्ञानी जी ने दो साल पहले बताया था कि हमने इन्सट्रक्शन्स दी है ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P VENKATASUBBAIAH): That is about peace keeping force.

SHRI RAM VILAS PASWAN: What about peace keeping fore?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: They have recruited them,

SHRI P C SETHI: As far as peace keeping force is concerned, we have already recruited three peace keeping battalions for the CRPF and another 5 CRPF battalions are going to be raised and we would try to see that more exearmy retired personnel can be placed in them.

As far as persons induling in communal violence are concerned, we have also written to the State Governmets that they should constitute special courts for this purpose; and I am also happy to report that many of the State Governments and many of the Chief Ministers who had come here have agreed that the special courts will be instituted for the trial of those persons who are involved in these communal troubles. Similarly, special courts have to be constituted in the case of atrocities which take place on Harijans and Adivasis. It has also been suggested that the National Integration Council should be made more active; it should be reorganised. The National Integration Council was re-constituted and re-activaed in 1980. But I agree that besides meetings of the three committees which had been constituted, the National Integration Council has not met since quite some time and we would certainly try to see that the National Integration Council is further broadbased and it is more activised so that in the real sense it can work out guidelines and proforma for the political parties; and they could work in a cohesive manner in order to solve the problem, It has also been observed that most of the minority Members of Parliament have given a representation to the Prime Minister in which one of the points which they have pointed out is that the amount which is paid as relief to the family of the deceased is not same at all places. In some places, for example, in Baroda, when I had been there, I came to know that the relief which they had given

was Rs. 1000 per person; in U.P, it was Rs. 5000; in Bihar, it was Rs. 10,000/-. Now, we are trying to evolve a procedure whereby a suitable amount is given as relief and it should be common and same in all the States so that everybody is properly rehabilitated. Apart from the relief to the family of the deceased, the property which they have lost should also be—particularly with regard to small persons—properly looked after and they should be given proper relief so that they could rehabilitate themselves.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : What about collective fine ?

SHRI P.C. SETHI : Some of the State Governments have gone into that, but we cannot issue a directive.

PROF. N.G. RANGA : You can advise them.

SHRI P.C. SETHI : We can certainly advise them about it. If it occurs again and again, we can advise them to think on imposing this collective fine also.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Very good.

SHRI P.C. SETHI : Restoration of law and order is the first priority of the Government. Several legal and administrative measures have been taken to eradicate lawlessness and to maintain conditions of peace all over the country. The State Governments have been advised to periodically review the law and order situation in the States and take effective measures to control it.

Shri Atal Bihari Vajpayee raised a point that it is wrong to deploy the Army frequently in aid of civil power. I agree with his sentiments. That is why, as far as deployment of the Army is concerned, in very rare cases we are doing it. But while we decided to increase the strength of the CRPF, when they were in power, they tried to reduce it. Six battalions were additionally raised after 1980, in our regime, five more have been sanctioned, while the Government into which the hon. Member, Shri Vajpayee was associated, reduced the strength of the CRPF by two battalions and wanted to go on reducing it further every year.

SHRI SURAJ BHAN : There was no need.

SHRI P.C. SETHI : I will show it. This was at a time when communal riots increased from 169 in 1976 to 188 in 1977 and 230 in 1978 and crimes against Scheduled Castes sky-rocketed from 5781 in 1976 to 14812 in 1978. While this was the actual position, the Annual Report for 1978-79 says "In the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the efforts of the Ministry were geared more fully towards prevention of violence on Harijans." It was, therefore, not fair on the part of Shri Vajpayee to say that the 1982-83 report does not give the true picture. I admit that the crime has, in certain respects, increased and it should have been told in a proper perspective.

I do not want to take time of the House in going in-to details on the crime situation. But I would like to point out that the amendment to the Dowry Prohibition Act, 1961, to which my colleague Shri Venkatasubbaiah referred, is under consideration. Similar is the position with regard to the Criminal Law (Amendment) Bill, 1980, which sought to make the law relating to rape more stringent. In both the cases, the Joint Committees have since presented their reports. The Government is giving final shape to the proposed legislation.

Another area of serious crime which has drawn a great deal of attention during the preceding year relates to the dacoities committed by the organised inter-State gangs operating in the ravine areas of Up, Madhya Pradesh and Rajasthan. Just now, Shri Jagpal Singhji also mentioned about it. It has been realised that besides strengthening coordinated police action against such gangs, it was equally important to find a permanent solution by bringing about a tangible change in the socio-economic condition of the area. As far as individual surrenders are concerned, they are not helping the situation. In 1973 when surrenders were adopted in Madhya Paradesh— it was a wholesale surrender of dacoits in MP, UP and Rajasthan—more than 600 dacoits had surrendered. After that for three years, there was no law and order situation in these parts of the country. Therefore, for the dacoits' problem more infrastructural

development with net work of roads and better communication frcilities will be required. Ravine reclamation, command area development and intensive agricultural and rural development programme have to be undertaken.

18.00 hrs.

Programmes for industrial development, specially those that may generate widespread activity, have to be created and the han. Members have rightly stressed the need to go deeper into the cause of crimes and increase in the capability of the police to prevent their commission and tacklo the crimes effectively and for that the police force has to be modernised and has to be given more vchicles and more modern and weapons. I fully share their concern in this regard and it would be agreed that crime is a complex social phenomenon and the first thing that appears necessary is people's association with the police. On the recommendations of the police chiefs, the State Governments are being advised to set up district level advisory committees for this purpose in which all the important social elements, in particular the women weaker sections, may be represented and the opinions of the ocal MLAs and MPs is also taken into consideration.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : One point of clarification, if you agree. You have rightly said that you are not in favour of surrender and you know the case of Phoolan Devi where the Madhya Pradesh Government encouraged this surrender and advertised that the criminals were alleging against the U.P. Government which were taking firm steps. Since they have said it, are you going to send instructions to Madhya Pradesh Government not to do it and openly say that you donot approve of what they have done ?

SHRI P.C. SETHI : I had called a meeting of the Chief Ministers of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh and I have discussed this problem. We have discussed with them and it was told to them that if surrenders have to be organised, it has to be done in a coordinated manner by all the State Governments to tackle the problem completely and individual surrenders would not solve the problem.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : You say that the surrender is not going to help it, does not reduce crime. Now you say that you want coordinated action for surrender.

SHRI P.C. SESHI : Prof. Chakraborty, what I have said is that individual surrenders are not going to solve the problem but if the total problem is solved and all the dacoits surrender by a coordinated action, then that is a different matter.

As far as the development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is concerned, there are two sides to the government approach for the betterment of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes-one side is the positive strategy for accelerating their development which is highlighted in Point 7 of the new 20-Point Programme and the other side is the protection for them against exploitation which again has its roots in social and economic deprivation in the case of Scheduled Castes and in the fact of their living in isolation. As far as the Fifth Plan was concerned, it was only for the creation of an infrastructure for the Scheduled Tribes. In the Sixth Plan so far as scheduled castes are concerned there is a massive outlay of more than Rs. 4500 crores and for the first time a substantial allocation has been made and a Special Central Assistance Plan has been drawn.

SHRI RAM VILAS PASWAN : 6,000 or 600 ?

SHRI P.C. SETHI : Rs. 4500 crores is the total outlay, out of which Rs. 600 crores will flow as a Special Control Assistance and the rest will come from the State Governments financial institutions. Similarly, in the Sixth plan outlay a part from different Ministries and state plans the Special Central Assistance for scheduled tribe development will be Rs. 470 crores. There has been substantial increase in the Special Central Assistance. The relative concentration of tribals in the area comprised in the four States of Madhya Pradesh, West Bengal, Orissa and Bihar calls for a close look and with this in view, a meeting of the Chief

Ministers of these States was called in February, 1983. 19 more primitive tribal groups have been identified whose development is fully funded by the Centre. 21 more pockets of tribal concentration with a tribal population of 1.46 lakhs have been brought under the Tribal sub-Plan.

Shri Ram Vilas Paswan said that the provision in the Sixth Plan for the Scheduled Tribes works out to Rs. 1.50 per person per day. This is not the factual position. Shri Paswan has taken into consideration only the Special Central Assistance. Actually, the bulk of the outlay for the Scheduled Tribes comes out of the Tribal sub-plans of the states. Therefore, the total amount is Rs. 4500 crores. Not only the Special Central Assistance, but the outlay from the State budgets and institutional finance go to benefit the Scheduled Tribes.

Actually, the Sixth Plan aims at not only creating the infrastructure, but raising the standard of the people below the poverty line, bringing them above the poverty line. It is said that the poverty line is going up. It is true that the poverty line is also going up, on account of the increase in prices. Efforts are being made and they are being helped by creating various institutions, like cooperative societies and marketing societies which are meant to help them.

As far as monitoring of these plans and the posting of proper officers is concerned, I would like to admit that this is lacking. Sometimes the officers posted in those areas are those who are undesirable. They have no aptitude to do this work. Therefore, proper posting of officers has to be done. Frequent transfer of these officers should not be done. So far as complete monitoring is concerned, we have sent to all State Governments as *pro forma*, which has to be filled up and sent to us every quarter so that we may monitor the progress of the Plan in every State every three months.

As far as crimes against Scheduled Castes is concerned, Shri Rajnath Sonkar Shastri and Shri Ram Vilas Paswan spoke of crimes against the Scheduled Castes. Actually, the most rapid increase in the crimes against the Scheduled Castes was from 1976 to 1978. But I want to admit that, although no lager scale violence has taken place recently, they are still continuing. Now the monetary relief for vcitims has been increased. For death and prmanent incapacitation the relief now is Rs. 10,000, as against Rs, 2,000 and Rs, 5,000 earlier in vogue. Similarly, graduated scales of relief have been fixed for other forms of suffering like rape etc. It is a matter of some gratification that in recent years a number of convictions have been obtained for crimess against Scheduled Castes by appointing Special Courts six and capital sentences and 136 life imprisonment sentences. We are impressing on the State Governments to ask for early trial and convictions. Whereas it took nearly three years to get conviction in the Belchi case, it has taken 9 months and 16 months in the Jetalpur and Palpur cases. More towns have been brought under the ambit of the Centrally Sponsored Scheme to convert dry latrines to water borne-ones, so that the demeaning practice of carrying night soil is ended.

श्री राम विलास पासवान : कफल्ता, देवली, साढूपुर और रामपुरा में इतनी बड़ी घटनाएं हुईं, मगर वहां कुछ नहीं हुआ। मैंने सजेस्चन दिया था कि होम मिनिस्ट्री में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट खोला जाए, जिसके बारे में मन्त्री महोदय ने कहा कि वह एक्टिव कनसिडरेशन में हैं। मैंने यह भी कहा था कि कैबिनेट की एक सब-कमेटी बनाई जाए, जो सर्विसिज में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के बैकलाग को पूरा करने और उन पर होने वाली स्ट्रासिटीज को रोकने के बारे में कार्यवाही करे।

श्री सूरज भान : कफल्ता के डी० एस० पी० को तो डीमोट कर दिया गया है, जो हरिजन है।

SHRI P.C. SETHI : As far as the creation of a separate department for Scheduled Castes and Tribes is concerned, I have alreody said it in the House that it is under the active consideration of the Government.

SHRI RAM VILAS PASWAN : How long is it under the consideration ?

SHRI SURAJ BHAN : We demand a separate Ministry.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He says it is under 'active' consideration.

SHRI SURAJ BHAN : Every time the Government gives the same reply..... (*interruptions*).

SHRI P.C. SETHI : Previously, it was under consideration; now it is under active consideration.

SHRI CHITTA BASU : When it will be under very active consideration ?

MR DEPUTY-SPEAKER : Then will come very very active consideaation.

श्री हीरालाल आर० परमार : देहुली हत्याकाण्ड में जो मारे गए थे उनके बच्चों को गोद लेने का आश्वासन दिया गया था लेकिन कोई भी नहीं है इस देश में ऐसा करने वाला ।

SHRI P.C. SETHI : Sir, I would like to remind the hon. Members, particularly, Shri Ram Vilas Paswan that.....

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : But you satisfy the Ruling Party Member first. He belongs to your family.

श्री हीरालाल आर० परमार : इसमें पार्टी का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है ।

SHRI P.C. SETHI : We can satisfy him.

I attend to the letters received from the hon. Members of Parliament on a very urgent basis and there is not a single day when I do not reply to at least 5 or 6 letters from Shri Ram Vilas Paswan, and I always forward them to the State Governments concerned or even to the other Departments if he addresses the letters to them. Similarly, I would like to remind all the other hon. Members.....

श्री राम विलास पासवान : रेप्लाई के लिए आपको धन्यवाद लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट को कन्डेम भी कीजिए कि वह ऐक्शन नहीं लेती है ।

(*Interruption*)

SHRI P.C. SETHI : Sir, many hon. Members have spoken in the Mandal Commission. As far as Mandal Commission is concerned, I would only like to say that hon. Members have not done justice to us. Sir, I have already said that had it not been our intention to go ahead with the Mandal Commission. The Government could have easily taken a stand stating that 'we now do not need Mandal Commission,' But we not only carried on with it, but received its Report, ultimately it was placed on the Table of the House. Now we have discussed it with the Chief Ministers and I assure the hon. Members that within two months the complicated questions with regard to the States where different castes and communities are included in their lists and on which Mandal Commission has suggested many things, the Secretaries Committee will sort them out, then we will process the whole thing and it will go to the Cabinet for decision, and we are not going to take long. The hon. Members should feel assured about it and should not doubt our intention.

श्री राम विलास पासवान : लेकिन आप इन प्रिंसिपल तो एग्री करते हैं रिजर्वेशन पालिसी से ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मानने की जो बात है वह कैबिनेट ही तय कर सकती है ।

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : What more do you expect ? He has given an assurance.

SHRI ERA AMBARASU : Will you consider a separate Ministry for Backward Classes ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : You give notice.

SHRI RAM VILAS PASWAN : When you are in the Chair, you are forward; when you came here you are backward.

SHRI P.C. SETHI : As far as the Centre-State relationship is concerned, the relations beween the Centre and the States are governed by the provisions of the Constitution. Under the Constitution, the States are in no

way dependent on the Union for the exercise of their legislative and executive authority. While providing autonomy to the States, the Constitution places in the hands of the Centre adequate powers to ensure the unity and integrity of the country.

Government have been periodically looking into the arrangements that govern the day-to-day working of provisions govering Centre State relations. The Administrative Reforms Commission looked into the matter and came to the conclusion that no constitutional amendment was necessary for ensuring proper and harmonious relations between the Centre and the States. This Administrative Reforms Commission was headed by no less a person than Shri Morarji Desai. The Central Government after consulting the State Govenments had agreed in 1975 with the aproach of the Commission. This was reiterated by the previous Government in 1978. The Seventh Finance Commission and also observed that the provisions governing financial relations had worked fairly and smoothly.

However, Government have been keeping this vital aspect in focus. The Zonal Councils have been revitalised and they have met more frequently during the last three years. But recently, looking to the fact that this demand is being raised by so many States and from so many places, the Prime Minister has constituted the Sarkaria Commission. I can assure the hon. Members that the terms of reference are in the process of being finalised and the other Members of the Commission will also be decided soon. She has also assured while answering questions in the other House that the States will be free to make their suggestions and even the Constitutional amendment is a part of the Constitution.

Therefore, there is nothing that debars the State Government from making any suggestions to the Commission.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : Not only that, when the terms of reference are finalised, they should amend the terms of reference and should direct the Sarkaria Commission—if they feel they should recommend for the amendment of the Constitution so that relation between the Centre and the States becomes more cordial.

MR. DEPUTY SPEAKER : Nobody is debarred. That is what he suggested.

SHRI P. C. SETHI : Some hon. Members spoke of the Police Commission's Report. We have released all these reports. We have no hestitation in discussing these reports in the House if the House so desires and the hon. Speaker permits. Most of them relate to the police matters in the States. But Shri Niren Ghosh has taken objection to the Government saying that the entire Police Commission Report is biased. By saying so, Shri Niren Ghosh has not done justice to us. All that the Government said was that at some places in the Report the Commission had in a wholesale manner condemned the political system and the whole police force. We have objected to this and not to the Police Commission's Report as such. Such a wholesale condemnation is hardly fair and does not improve the morale of the force and those who are doing good work.

As far as the modernisation and upgradation of police administration is concerned, I would like to say that now more funds are being given to the State Governments for the modernisation of the police force and also modernisation of the vehicles and other things which they have got. Moreover, the Seventh Finance Commission has recommended substantial outlays for upgraduation of police housing programme in the police and the Central assistance for the purpose of upgradation is made available to States. The same is available for housing under this scheme to as many as 15 States.

The question of official language Hindi versus other languages was also raised here. According Article 343 of the Constitution, Hindi is the official language of the Union. Provision has been made for the continued use of English language for official purposes of the Union under Section 3(1) of the Official Languages Act 1963. Hindi or English language is being used in the Central Government offices as well as undertakings. As far as the other languages spoken in the different parts of the country are concerned, they are all part of the Eighth Schedule. The House would like to recollect the words of late Pandit Jawaharlal Nehru who has said :

"That they are all national languages and there is no question of calling them the regional languages."

SHRI CHITTA BASU : They are not in the Eighth Schedule.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : They are.

SHRI RAM VILAS PASWAN : It has been said that Hindi shall be the official language and English shall be the associate language.

SHRI P. C. SETHI : In the Schedule we have accepted fifteen languages.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : It is very sensitive. You have said official language. But the question is whether other languages are at par and will have the same privileges that you confer on Hindi; whether it may be the link language ? You must be specific. This is what we have been demanding. We are not opposed to Hindi, but the question is whether other languages should be treated at par and will enjoy the same privileges that you confer on Hindi ?

SHRI P.C. SETHI: Sir, as far as the other languages are concerned, I think, Prof. Chakraborty would agree that Tamil would not be receiving the same attention in West Bengal as Bengali receives. Similarey, Bengali would not receive the same attention in Tamil Nadu as Tamil does. So, these are the complications.

But as far as the respective languages are concerned, they are the official languages of those areas and all the communications are being done by those States in those languages. (*Interruptions.*)

Now, only two points remain. Dr. Subramaniam Swamy has raised here a point about the library programme in West Bengal.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: I am on a Point of Order. How does it come under Home?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Why do you object?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: I am not objecting but I am in a position to meet all the points. But.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is your point of order?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Sir, we are discussing the Demands for Grants for the Ministry of Home Affairs. Dr. Swamy has raised something which has nothing to do with Home but with Education. I do not mind if it comes under Education. How is the Home Minister going to answer on education, syllabus and all that.

PROF. K.K. TEWARY (Buxar): Under what rule have you raised the Point of Order?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Under Rule 376. (*Interruptions.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. He has made a Point of Order. But I say, there is no point of order. Any hon. Member who speaks can express his own view in as free a manner as possible. And, therefore, he has referred to education or anything, here. And you would see that every hon. Member does not stick only to the subject-matter.

Further, he cannot also dictate the Minister not to reply to the hon. Member.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: I am not dictating. You should be very particular before giving the ruling.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have given the ruling. The Minister can reply.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Tomorrow, we will be speaking on Irrigation.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is left to the Minister.

(*Interruptions.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please listen. It is the joint responsibility of the Cabinet.

SHRI P.C. SETHI: Prof. Chakraborty, you should have patience.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, you can reply now. You are entitled to and you can reply to Dr. Swamy.

(*Interruptions.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is that you want?

(*Interruptions.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You want no reply to Dr. Swamy? You have no right. Please sit down.

(*Interruptions.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER :I have told you that you cannot dictate. You cannot dictate to the Minister.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Does it come under the Home Ministry ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down. He will meet your objections. Please sit down.

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Why do you give this ruling, Sir ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : What is the ruling that I have given ? I have not given any ruling. I have made some observations on your point of order.

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Sir, you go through the record of your observations on a previous occasion. Your ruling is something like that the hon. Member cannot speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I said, Dr. Subramaniam Swamy can express his own view in this House...

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : On what ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : And the Minister can also reply to his view.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down. It applies to both of them. Leave it. You can reply now.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Your ruling is not correct.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down.

(*Interruptions*).

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: What is this ruling ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not the way. I am not budging to anybody. Please sit down. I am not permitting anybody. Don't question my ruling, if it is a ruling.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Why is everybody getting up. You don't want to...

(*Interruptions*)

SHRI P.C. SETHI : Mr. Halder, kindly hear me.

SHRI M.M LAWRENCE (Idukki) : There cannot .be a double-standard in this House. You have to stick to the ruling.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: I warn you and I warn this House also that this will be used as a precedent. And I warn the Chair. (*Interruptions.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I tell you, under any situation, the Chair will not budge.

SHRI SATYADHAN CHAKRABORTY*

(*Interruptions*)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : This is a State subject.

SHRI P.C. SETHI : Kindly hea me.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is all right Please sit down.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : You should not do like that.

(*Interruptions*)

PROF. K.K. TEWARY : On a point of order, Sir. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER : I am not permitting anybody on this. The Minister only will reply, (*Interruptions*)

All of you please sit down. (*Interuptions*)

I will go through the records if there is any aspersion...(*Interruptions*) ** Don't record anything.

(*Interruptions*) **

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Let the hon. Members hear patiently what the Home Minister is going to say.

(*Interruptions*) **

---

*Expunged as ordered by the Chair.
**Not recorded.

MR. DEPUTY SPEAKER : You give notice on this. I do not know how Mr. Satyasadhan Chakraborty knows what the Home Minister is going to say. He is yet to reply. (*Interruptions*)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Under article 356 of the Constitution, the Home Miuistry has every right to see that the constitutional provisions are being maintained, I spoke on dis-information. It has nothing to do with education. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER : The Minister can reply. Why are you so much intolerent of any view that is expressed here ? If you have got a firm conviction on any view, you should not be afraid. (*Interruptions*) You please sit down. You will not sit down. You keep standing. (*Interruptions*)

SHRI P.C. SETHI : It is entirely within the purview of the State Government as to what type of libraries they are opening. Certainly, whatever Mr. Subrmaniam Swamy has spoken, we will forward it to them with a request that in these libraries something about the national movement and the national leaders should also be there.

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : How do you know that they are not already there ? (*Interruptions*) Mr. Subramaniam Swamy has spoken because I am connected with this...(*Interruptions*) Education is in the Concurrent List...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER : He is only referring to the West Bengal Government.

(*Interruptions*)

PROF. K.K. TEWARY : On a point of order, Sir. The Home Minister with reference to Mr. Subramaniam Swamy's observation has said that he will refer all those details to the West Bengal Government and also recommend to them that freedom struggle should also be made known to the Children West Bengal...(*Interruptions*)

That should be made known.

SHRI ERA ANBARASU : I am on a point of order.

PROF. K.K. TEWARY : Whether the Central Government will intervene and do something to set up an ideology through education.

MR. DEPUTY SPEAKER : You ask a clarification from the Hon. Minister.

SHRI RAMAVATAR SHAST I : He does not know A, B, C, D of this.

MR. DEPUTY SPEAKER : There is a point of order. You ask for some time. I request Mr. Ramavatar Shastri to sit down. This is not the way. I am so sorry. Please sit down. Certain points you can express. But this is not the way.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : I am on a point of clarification. I am satisfied with what the Hon. Minister said. The Hon. Minister said he would write with the request that the freedom struggle should also be included. But he must make it clear...

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : You should hear everybody.

MR. DEPUTY SPEAKER : When the Hon. Minister replies and when an Hon. Member raises any issue for clarification and the Minister yields, then the chair cannot stop it. Dr. Swamy has asked for clarification and the Hon. Minister has yielded. Therefore, I will not allow any body else to speak. The Hon. Minister has yielded. I have io allow him. I have to give him protection. I have also to do something with regard to you.

Dr. Subramaniam Swamy.

SHRI BHOGENDRA JHA : I am on a point of order. Every Member must rise from his seat if he has anything to say. Dr. Swamy must rise from his seat and speak.

MR. DEPUTY SPEAKER : There is no point of order.

SHRI BHOGENDRA JHA : Amend the rules.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER : I have ruled that the point of order is out of order. My ruling you cannot question. I have ruled it out of order.

Dr. Subramaniam Swamy.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Anyway, 1 support what he said. It is reserved for the Janata Party. In the absence of Prof.

Madhu Dandavate, I am functioning as Leader of the Janata Party. It i a serious point, I want to make sure that when the Hon. Minister writes, he should say that freedom struggle should also be including freedom struggle of India and not of any other country. That should be made clear.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : You are the Home Minister. He is yielding.

You are the Home Minister. On the basis of what are you going to write to the State Government ? That way, I can bring any charge .. (*Interruptions*)

SHRI C.T. DHANDAPANI : Suppose I refer something about Tamil Nadu Government in the House; it is the duty of the Central Government to write to the Tamil Nadu Government. (*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : That will be opening the Pandora's Box. You are the Home Minister. Under what constitutional provision have you been authorised to write to a State Government on education ? On the basis of an allegation made in the House ?

SHRI C.T. DHANDAPANI : 'Education' comes under the concurrent List. Both centre and the states have powers...

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : To whom are you going to write ? Under what Constitutional provision ? You are the Home Minister. On what basis, on the basis of what allegation, are you going to write ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the Minister is going to reply.

SHRI RAM VILAS PASWAN : It is already 6.35 p.m. You have to adjourn the House. We will hear the Minister tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please be serious. He has asked for clarifications. You do not want the Minister to reply ?

SHRI P.C. SETHI : I think, Prof. Chakraborty knows...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Shastri, you are the seniormost trouble-giving Member.

SHRI P.C. SETHI : I think, Prof. Chakraborty knows that 'Education' is a concurrent subject, and I have not said anything which should offend him or the West Bengal Government. But if some matter of importance is raised in the House by an hon. leader of the Opposition, then it is my duty to bring it to the notice of the Chief Minister, and that is what I have said. This should not offend any one of you.

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly) : One clarification.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am not permitting. The Minister is not yielding.

PROF. RUP CHAND PAL : You are unfair to me.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am fair to all; especially to you I am very fair. The Minister is not yielding. I cannot permit you. Nothing will go on record because the Minister is not yielding.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : What can I do ? I am also in a helpless position like you. The Minister will reply.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : When they were in power in Tamil Nadu, they did not bring in such a charge. You ask him, Sir, why in 1977-78 they did not bring in such a charge.

SHRI P.C. SETHI : If Prof. Chakraborty raises something in the House about the Janata Party, I will write to the Chief of the Janata Party.

Mr. Faleiro has made a charge against Scindia Devasthan Trust about which he has submitted the papers to the Hon. Speaker. I have no inside knowledge about this. All I can say is that we will make all enquiries about this matter and we shall keep him informed.

Mr. Chinnaswamy has said.....

**Not recorded

SHRI ERA ANBARASU (Chengalpattu): Will it be a CBI inquiry ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down.

SHRI P.C. SETHI : Mr. Chinnaswamy has said that the MLAs should also be associated with voting in the election of president. MLAs of state are being associated.

AN HON. MEMBER : One clarification.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : No clarifications. Are you replying ?..... The Minister is not replying.

I shall now put all the Cut Motions. The other things will not go on record.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put all the Cut Motions moved to the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs to the vote of the House...

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : जे० एन० यू० में हरिजन छात्रों पर हो रहे अत्याचार के बारे में आपने कुछ नहीं कहा ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने कहा था आप मुझे लिखेंगे । I have told you that you should write to me.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER : I shall now put all the cut motions moved to the Demands of the Ministry of Home Affairs to the vote of the House.

Unless any hon. Member desires that his cut motion should be put separately, I shall put all the cut motions together to the vote of the House.

All The Cut Motions were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now I shall put the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs to the vote of the House

The question is :

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India TO COMPLETE the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the years ending the 31st day of March, 1984, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 50 to 60 relating to the Ministry of Home Affairs."

The motton was adopted.

DEMANDS FOR GRANTS, 1983-84 IN RESPECT OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS VOTED BY LOK SABHA

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 18th March, 1983		Amount of Demand for Grant voted by the House	
1	2	3		4	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
50.	Ministry of Home Affairs	83,57,000	...	4,17,84,000	...
51.	Cabinet	73,46,000	...	3,67,33,000	...

**Not recorded

1	2	3		4	
52.	Department of Personal and Administrative Reforms	1,90,25,000	3,25,000	9,51,27,000	16,23,000
53.	Police	64,06,88,000	2,95,58,000	320,34,40,000	14,77,91,000
54.	Census	2,57,26,000	...	12,86,32,000	...
55.	Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	75,08,40,000	33,68,68,000	359,81,86,000	142,39,45,000
56.	Delhi	48,37,58,000	41,71,45,000	241,87,90,000	177,24,65,000
57.	Chandigarh	8,22,43,000	3,84,38,000	41,12,15,000	19,21,88,000
58.	Andaman and Nicobar Islands	6,71,27,000	4,66,28,000	33,56,38,000	23,31,43,000
59.	Dadra and Nagar Haveli	82,92,000	89,32,000	4,14,60,000	4,46,61,000
60.	Lakshadweep	217,10,000	33,79,000	10,85,49,000	1,68,97,000

18.43 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on, Wednesday, April 13, 1983/ Chaitra 23, 1905 (Saka).

Printed at Samrat Press, 7118, Pahari Dhiraj, Delhi-110006.